वर्तमान

कमल ज्योति

तेरा वैभव अमर रहे माँ!

मोदी की गारंटी

विकसित भारत विशेषांक

₹20

भारतीय जनता पार्टी
महिला मोर्चा

वर्तमान

कमल ज्योति

संरक्षक

श्री भूपेन्द्र सिंह

सम्पादक

अरुण कान्त त्रिपाठी

प्रबन्ध/कार्यकारी सम्पादक

राजकुमार

प्रकाशक

प्रो0 श्याम नन्दन सिंह

पृष्ठ संयोजक

ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग

लखनऊ – 1

फोन :– 0522–2200187

फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक

नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र,
राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

www.up.bjp.org
bjpkamaljyoti
bjpkamaljyoti
@bjpkamaljyoti

सम्पादकीय

विकसित भारत का संकल्प!

पृथ्वी का सबसे पुराना सनातन, राष्ट्र विश्व गुरू था कालक्रमेण गुलाम हुआ। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत कंगाल, गरीब, देशों की पंक्ति में खड़ा हो गया पर आजादी का संग्राम जारी रहा। हम आजाद हुए और अमृतकाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है।

विकसित भारत के संकल्प के बारे में मोदी जी कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के जीवन में, इतिहास एक मौका देता है। जब राष्ट्र अपनी विकास यात्रा में तेजी से प्रगति कर सकता है। भारत में "अभी अमृत काल चल रहा है" और "यह भारत के इतिहास का वह कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है"। उन्होंने आस–पास के कई देशों का उदाहरण दिया जिन्होंने एक निर्धारित समय सीमा में इतनी लंबी छलांग लगाई कि विकसित राष्ट्र बन गए। भारत के लिए यही समय है, सही समय है। उन्होंने कहा कि इस अमृत काल के प्रत्येक क्षण का उपयोग किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने प्रेरणा – स्रोत के रूप में स्वतंत्रता के लिए गौरवशाली संघर्ष को याद किया। उस समय के प्रत्येक प्रयास जैसे कि सत्याग्रह, क्रांतिकारी पथ, असहयोग, स्वदेशी और सामाजिक तथा शैक्षिक सुधार स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। उस काल में काशी, लखनऊ, विश्व भारती, गुजरात विद्यापीठ, नागपुर विश्वविद्यालय, अन्नामलाई, आंध्र और केरल विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों ने राष्ट्र की चेतना को मजबूत किया। देश की आजादी के लिए समर्पित युवाओं की एक पूरी पीढ़ी सामने आई, जिसका हर प्रयास आजादी के लक्ष्य पर केंद्रित था। आज हर संस्था, हर व्यक्ति को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि उनके हर प्रयास और कार्य विकसित भारत के लिए होगा। आपके लक्ष्यों, आपके संकल्पों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए– **"विकसित भारत"**। शिक्षक और विश्वविद्यालय भारत को तेज गति से एक विकसित देश बनाने के तरीके खोजने पर विचार करें और एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में सुधार के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान भी करें।

जब नागरिक अपनी भूमिका में अपना कर्तव्य निभाना शुरू कर देते हैं, तो देश आगे बढ़ता है। जल संरक्षण, बिजली की बचत, खेती में कम रसायनों का उपयोग और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उदाहरण है। शिक्षाविद् समुदाय से स्वच्छता अभियान को नई ऊर्जा देने, जीवनशैली के मुद्दों से निपटने और युवाओं द्वारा मोबाइल फोन से परे दुनिया की खोज करने के तरीके सुझाने को कहा। शिक्षकों से छात्रों के लिए आदर्श बनने को कहा। सामाजिक सोच शासन में भी परिलक्षित होती है और उपस्थित लोगों से यह भी कहा कि डिग्री धारकों के पास कम से कम एक व्यावसायिक कौशल होना चाहिए। आपको हर वर्ग, हर संस्थान और राज्य स्तर पर इन विषयों पर विचार–मंथन की एक व्यापक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए।

देश की तेजी से बढ़ती आबादी में युवाओं की संख्या को देखते हुए भारत आने वाले 25–30 वर्षों तक कामकाजी उम्र की आबादी के मामले में अग्रणी बनने जा रहा है और दुनिया इस बात को समझती है। श्री मोदी ने कहा कि युवा शक्ति बदलाव की वाहक भी है और बदलाव की लाभार्थी भी है। अगले 25 साल आज के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में युवाओं के करियर के लिए निर्णायक होंगे। ये युवा ही हैं जो भविष्य में नए परिवार और नया समाज बनाएंगे, उन्हें ही यह तय करने का अधिकार है कि एक विकसित भारत कैसा होना चाहिए। इसी भावना के साथ सरकार देश के हर युवा को विकसित भारत की कार्ययोजना से जोड़ना चाहती है।

प्रगति का रोडमैप अकेले सरकार नहीं बल्कि राष्ट्र तय करेगा। देश के प्रत्येक नागरिक की इसमें भागीदारी होगी और सक्रिय भागीदारी होगी। सबका प्रयास की शक्ति को उजागर करते हुए स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया अभियान, कोरोना महामारी के दौरान लचीलापन और वोकल फॉर लोकल का है। प्रधानमंत्री ने कहा, "सबका प्रयास से ही विकसित भारत का निर्माण होना है।" आइये मिलकर विकसित नव्य–भव्य सांस्कृतिक राष्ट्र को संवारने बनाने में अपना योगदान समर्पित करें।

bjpkamaljyoti@gmail.com

देश विकसित भारत बनकर रहेगाः मोदी

प्रधानमंत्री काशी आए। मंत्रोच्चार और शंखध्वनि के बीच बाबतपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री सीधे कटिंग मेमोरियल ग्राउंड गए और विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया।

दो दिवसीय प्रवास में सर्वेद मन्दिर का उद्घाटन, "**तमिल संगमम्**" सहित अनेक कार्यक्रम हुए। नमो घाट पर मौजूद तमिलनाडु के लोगों ने उसे हेडफोन पर सुना। प्रधानमंत्री ने एआई को नई शुरूआत बताया और कहा कि इसके जरिये पहली बार तमिलनाडु से आए 1400 परिवारजनों और देश की जनता से जुड़ रहे हैं। जो कुछ कह रहे हैं, उसका अनुवाद तमिल में हो रहा है। आप भी मोबाइल के जरिये सीधे जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने काशी और तमिलनाडु की सभ्यता, संस्कृति को एक बताया और कहा कि तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है कि महादेव के एक घर से दूसरे घर आना है। मदुरैमीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प और सपना साकार होगा। भारत को मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी। संकल्प यात्रा भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का बीज है, जो अगले 25 साल में वट वृक्ष बनकर तैयार हो जाएगा। यह यात्रा मेरे कार्यों की परीक्षा भी है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लाभार्थियों के जरिये मिल रहा है। इससे संतोष मिलता है। आत्मविश्वास बढ़ता है।

काशीवासियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि मैं, आपके सेवक के नाते तो कार्य करूंगा ही, मगर आपने जो देश का काम दिया है, उसमें भी महादेव के आशीर्वाद से कभी पीछे नहीं रहूंगा। काशी के सांसद के नाते मेरा दायित्व बनता था कि इस कार्यक्रम में आपके सेवक के रूप में हिस्सा लूं। देश में सरकारें बहुत आईं। योजनाएं भी बहुत बनीं। बड़ी–बड़ी बातें हुईं, मगर सोचने वाली बात यह है कि सरकार जो योजना बनाती है। जिसके लिए बनाती है और जिस लक्ष्य के लिए बनाती है, क्या वो बिना किसी परेशानी के सही समय पर लाभार्थियों तक पहुंच रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि योजनाओं के लिए जनता को नहीं बल्कि सरकार को जनता के पास पहुंचना होगा। इसी संकल्प के साथ यात्रा पूरे देश में चलाई जा रही है। इसके जरिये हमने तय किया है कि सरकार लाभार्थियों से जाकर मिलेगी और उनके अनुभव पूछेगी। इससे हमारे कार्यों का हिसाब–किताब हो जाएगा। ये संकल्प यात्रा एक प्रकार से मेरी कसौटी और परीक्षा भी है। इससे तय होगा कि मैंने जो कहा और जो कार्य कर रहा हूं, उसके बारे में जनता क्या कह रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्हें योजनाओं के लाभार्थियों से आशीर्वाद मिलता और सरकारी अफसरों का आत्मबल बढ़ता है। सरकारी कागजों पर दस्तखत करके योजनाएं लागू करना सरकारी काम होता है, मगर जब उस योजना से किसी गरीब को फायदा मिलता है तो अफसरों को भी आत्मसंतोष मिलता है। अच्छा फीडबैक उत्साह बढ़ाता है।

विकसित भारत बनाने का संकल्प लें 140 करोड़ देशवासी

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर 140 करोड़ देशवासी इस संकल्प से भर जाएं कि अब देश को आगे ले जाना है। हर किसी की जिंदगी बदलनी है तो अगले 25 वर्षों में देश विकसित भारत बनकर रहेगा। देश विकसित बन जाएगा तो इस वट वृक्ष की छाया आपके ही बच्चों को मिलेगी। संकल्प लेना और मन बनाना होगा। मन बन जाएगा तो मंजिल दूर नहीं होगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा हम सबका बहुत बड़ा संकल्प है, जिसे हमें सिद्ध करना है। भारत विकसित हो जाएगा तो तमाम मुसीबतों का नामो निशान नहीं होगा। हम मुसीबतों से मुक्त हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दक्षिण से उत्तर का अद्भुत संगम हो रहा है। नरेंद्र मोदी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करता है। काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने वाले 1400 लोगों को सात समूहों में बांटा जाएगा। काशी विश्वनाथ के साथ ही अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का दर्शन–पूजन कराया जाएगा। प्रयागराज और मथुरा भी ले जाया जाएगा। 15 दिनों तक अद्भुत अलौकिक नजारा देखने को मिलेगा। इससे पहले केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी तमिल संगमम् की खासियत बताई।

कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई : नरेन्द्र

तीन राज्यों में शानदार जीत के बाद कार्यकर्ता और नेता बेहद उत्साहित हैं।

मोदी ने कार्यकर्ताओं को कहा, 'भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अब तेजी से एकजुट होने का प्रयास कर रही हैं। समाज में खाई पैदा करने वाले अब नए मौके तलाशेंगे। हमें उनसे मुकाबला भी करना है। उनका जवाब भी देना है। लेकिन उससे भी बढ़कर हमें जनता की रीढ़ को बनाए रखना है।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा जब भी कोई चुनाव लड़ती है चाहे राज्य का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा नेतृत्व को संभाला है और उस चैलेंज को स्वीकार किया है। इस चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश ने समझ लिया है कि अगर कोई गांव को कोई मजबूती दे सकता है तो वह PM नरेंद्र मोदी हैं। इन नतीजों ने संदेश दिया है कि गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति को कोई सम्मान दे सकता है तो वह प्रधानमंत्री मोदी हैं।

'सुधर जाइए, वरना जनता चुन–चुनकर साफ कर देगी'

पीएम मोदी ने आगे कहा, आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगति और जनकल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं। जब भी विकास होता है, कांग्रेस और उसके साथी विरोध करते हैं। जब हम वंदे भारत लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी मजाक उड़ाते हैं, जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं तो वे रुकावट डालते हैं, जब हम नल से जल की योजना बनाते हैं तो वे इस पर रोड़ा डालते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है। सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन–चुनकर साफ कर देगी।

'जनता का दिल जीतने के लिए चाहिए राष्ट्रसेवा का जज्बा'

मोदी ने कहा, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों पर प्रहार करने में जुटे हैं, वे समझ लें कि ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जनसमर्थन है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए बड़ा सबक है। ये सबक है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्रसेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडिया गठबंधन में वो रत्ती भर भी नजर नहीं आता है।

> **जनता का दिल जीतने के लिए चाहिए राष्ट्रसेवा का जज्बा'**

'जीत ने दे दी 2024 की हैट्रिक की गारंटी'

कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। आज के जनादेश ने यह भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन तीन बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है, तो वह भाजपा ही है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो

अभियान छेड़ रखा है, उसको भारी जनसमर्थन मिल रहा है। यह उन दलों, नेताओं को मतदाता की साफ–साफ चेतावनी है, जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करते। उन लोगों को आज देश की जनता ने साफ–साफ संदेश दे दिया है।

मोदी ने कहा, भाजपा ने सेवा और सुशासन की राजनीति का नया मॉडल देश के सामने पेश किया है। हमारी नीति और निर्णयों के मूल में देश और देशवासी हैं। इसलिए भाजपा सरकारें सिर्फ नीतियां नहीं बनाती, बल्कि हर हकदार हर लाभार्थी तक वह पहुंचे, यह भी सुनिश्चित करती है। भाजपा परफॉर्मेंस और डिलीवरी की राजनीति देश के सामने लेकर आई है। भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है, जनहित और राष्ट्रहित क्या है। दूध और पानी का भेदभाव देश जानता है। जैसे–तैसे जीतने के लिए हवा–हवाई बातें करना और लोभ लालच की घोषणा करना, यह मतदाता को पसंद नहीं आता है। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप चाहिए। एक भरोसा चाहिए। भारत का वोटर यह जानता है जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है। हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वह भाजपा को चुन रहा है। लगातार चुन रहा है।

'जीत ने दे दी 2024 की हैट्रिक की गारंटी'

उन्होंने कहा, 'इन परिणामों की गूंज दूर तक जाएगी। पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गूंज सुनाई देगी। यह चुनाव परिणाम दुनियाभर के निवेशकों को नया भरोसा देगा। आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत को जो सपना हमने देखा है, उसे लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। आज दुनिया देख रही है कि भारत का लोकतंत्र और मतदाता कितने परिपक्व हैं। आज दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूर्ण बहुमत के लिए स्थिर सरकार के लिए सोझ समझकर वोट कर रही है।' 'मैं तेलंगाना की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हर चुनाव में तेलंगाना में भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मैं तेलंगाना के लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा आपकी सेवा में कोई कोर–कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।'

'चुनाव नतीजों ने एक बात और स्पष्ट की है। देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है, वह सरकारें सत्ता से बाहर हुई हैं। चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो। ये सभी सरकारें पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोपों में घिरी हुई थीं। परिणाम यह हुआ कि ये दल सत्ता से बाहर हैं। देश में भरोसा बढ़ रहा है कि भाजपा उसकी आकांक्षा को समझता है, उसके लिए काम करता है।' प्रधानमंत्री ने आगे कहा, 'जिस कांग्रेस सरकार ने आदिवासी समाज को पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने उसका सफाया कर दिया। यही भावना हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान में देखी है। इन राज्यों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। आदिवासी समाज आज विकास के लिए आकांक्षी है। उसे भरोसा है कि इस आकांक्षा को सिर्फ और सिर्फ भाजपा पूरी कर सकती है।'

'नारी शक्ति का विकास भाजपा के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। इस चुनाव में माताओं–बहनों–बेटियों ने भाजपा की जीत की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली थी। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की बहन–बेटी से यही कहूंगा कि भाजपा ने आपसे जो वादे किए हैं, वो शत प्रतिशत पूरे किए जाएंगे। यह मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी।' मेरी माताओं–बहनों–बेटियों, युवा साथियों, किसानों ने जो निर्णय दिया है, उनके सामने मैं नतमस्तक हूं। इस देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिश हुई। लेकिन मैं लगातार कहता था कि मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। जब मैं चार जातियों की बात करता हूं हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। इन चार जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या से हमारे साथी इसी वर्ग में आते हैं। इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोडमैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। आज हर गरीब कह रहा है.. वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है..यह चुनाव हर किसान जीता है। आज हर आदिवासी भाई बहन यह सोचकर खुश है.. जिसे उसने वोट दिया वह विजयी है।'

मोदी है, तो मुमकिन है: नड्डा

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की ऐतिहासिक जीत आयोजित अभिनंदन समारोह को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने संबोधित किया। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन किया और भाजपा की इस जीत का श्रेच प्रधानमंत्री जी के कालजयी नेतृत्व, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और माननीय प्रधानमंत्री जी एवं भाजपा के प्रति जनता के अपार प्यार, समर्थन और आशीर्वाद को दिया।

कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजनाथ सिंह जी सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता एवं भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिलने पर जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि "देश में किसी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है – वह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी है। विधानसभा चुनावों के नतीजों ने एक और स्पष्ट संदेश दिया है कि "मोदी है, तो मुमकिन है।"

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। इसके लिए मैं अपनी ओर से और पार्टी के करोड़ों –कार्यकर्ताओं की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति अभार प्रकट करता हूँ। साथ ही, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की जनता को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है।

श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है चाहे वो देश का चुनाव हो या प्रदेश का हो, समय अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व को संभाला है और चुनौतियों को स्वीकार किया है। उनके अथक प्रयास और मेहनत से संगठन एवं चुनाव की रणनीतियों की छोटी–छोटी बारीकियों को ध्यान में रखकर चुनावी नतीजों को बेहतर परिणाम तक पहुंचाया है।

देश ने समझ लिया है कि अगर कोई गांवों को मजबूती दे सकता है, तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी दे सकते हैं। गांव, गरीब, वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी भाई–बहनों को समाज की मुख्यधारा में कोई ला सकता है, तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ही ला सकते हैं।

सिर्फ इस बार हुए विधानसभा चुनावों में नहीं, बल्कि इससे पहले हुए अनेक चुनावों में उन्होंने बेहतर परिणाम दिलाया है।

राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम को रेखांकित करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनावों के नतीजों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश ने समझ लिया है कि अगर कोई गांवों को मजबूती दे सकता है, तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी दे सकते हैं। गांव, गरीब, वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी भाई बहनों को समाज की मुख्यधारा में कोई ला सकता है, तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ही ला सकते हैं। देश में सबको विश्वास है कि चाहे महिला सशक्तिकरण हो या चाहे किसानों के सम्मान की बात हो, या युवाओं की आकांक्षाओं एवं इच्छाओं को साकार करने की बात हो, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ही सबको साथ लेकर सबके सपनों को साकार करेंगे।

श्री नड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणामों ने एक और संदेश दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र को बढ़ाया है। लेकिन, कांग्रेस ने इस चुनाव में जिस प्रकार से देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पर अभद्र टिप्पणियां की है, वह न सिर्फ असंसदीय है, बल्कि बहुत ही निम्न स्तरीय राजनीति एवं मानसिकता का भी प्रतीक है। कांग्रेस नेताओं ने ऐसी टिप्पणी की है कि उसे दोहराना भी उचित नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री पर ऐसी गंदी टिप्पणियां करते समय भी यह भी ध्यान में नहीं रखा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी को गाली देने का मतलब पिछड़ी जाति (ओबीसी) को गाली देना है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक (कांग्रेस) नेता हैं, जो कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। उनकी रस्सी जल गयी किंतु बल नहीं गया है। इस चुनाव के नतीजों ने ऐसे नेताओं के बल एक बार नहीं, बल्कि अनेकों पर खत्म किया है।

श्री नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत को सराहते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय

"विकास" का पलड़ा इंडी एलायंस की **"जातिवाद और तुष्टिकरण"** की राजनीति पर भारी है। इंडी एलायंस ने इस चुनावों में जातिवाद फैलाने, समाज को खंडित करने, देश को बांटने की कोशिश की और तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया है, लेकिन देश एवं प्रदेश की जनता ने जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को सिरे से नकार दिया है।

I-N-D-I- एलायंस ने चुनावों में जातिवाद फैलाने, समाज को खंडित करने, देश को बांटने की कोशिश की और तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया लेकिन देश एवं प्रदेश की जनता ने जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को सिरे से नकार दिया है।

आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनावों में नए–नए जोश और नारों के साथ I-N-D-I- एलायंस के नेता घड़ियाली आंसू बहाकर ओबीसी–ओबीसी का रट लगाए हुए थे। I-N-D-I- एलयांस के नेता भूल जाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। उन्होंने समाज में सबका साथ और सबका विकास का प्रण लेकर सबका साथ, सबका

की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरी लगन एवं मेहनत से चुनाव में उतर कर पार्टी को जीत दिलायी है। मीडिया पूछती थी कि भाजपा की रणनीति क्या है? उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की एक ही रणनीति है कि पार्टी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ता दिन–रात जमीन पर मेहनत करते हैं। यह उसी का परिणाम है कि विधानसभा चुनावों में पार्टी को बेहतर परिणाम मिला है। इसके लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। उन्होंने जनता को परमेश्वर की संज्ञा देते हुए कहा कि भाजपा को किसी जाति, समुदाय या समूह का नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग का आशीर्वाद मिला है, इसके लिए मैं उनके प्रति अभार प्रकट करता हूँ।

अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य सभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा का जवाब दिया। चर्चा के बाद सदन ने बिल को पारित कर दिया। लोक सभा पहले ही दोनों विधेयकों को पारित कर चुकी है।

गृह मंत्री ने कहा कि आज का दिन जम्मू और कश्मीर और भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अंकित होगा जब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लिए गए निर्णय के तहत धारा 370 को समाप्त करने और जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन की मंशा और प्रक्रिया को संवैधानिक घोषित किया है। इन विधेयकों के बारे में उठाए गए सवाल न्याय के लिए नहीं थे बल्कि मोदी जी द्वारा लिए गए निर्णय को लंबित करने के इरादे से किए गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया और कई चीज़ों को, जिन्हें 1950 से हम बताते रहे, अमली जामा पहना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज माना कि जम्मू और कश्मीर के पास कभी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी और अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। श्री शाह ने कहा कि अगर धारा 370 न्यायिक और ज़रूरी थी, तो इसके सामने टेंपरेरी शब्द क्यों लिखा गया। जो कहते हैं कि धारा 370 स्थायी है, वो संविधान और संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान और देश की संसद को धारा 370 को हटाने का पूरा अधिकार है।

अब जम्मू-कश्मीर के युवाओं के हाथों में बन्दूक नहीं लैपटॉप होंगे, मोदी जी के नेतृत्व में नए कश्मीर बनने की शुरुआत हो गयी है

सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को चुनौती देना ठीक नहीं है और ये पूर्ण रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप है। श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 (3) के प्रावधान को संविधान सभा ने ही तय किया और ये कहा गया कि भारत के माननीय राष्ट्रपति धारा 370 में सुधार कर सकते हैं, इस पर रोक लगा सकते हैं और इसे संविधान से बाहर भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी माना कि 5 अगस्त, 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति जी को अनुच्छेद 370 का संचालन बंद करने का पूर्ण अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि धारा 370 के तहत मिली हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय एकतरफा सूचना जारी कर सकते हैं जिसे संसद के दोनों सदनों का साधारण बहुमत से अनुमोदन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि जब धारा 370 समाप्त हो चुकी है, तो ऐसे में जम्मू और कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता

है। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में चुनाव कराने के लिए भी निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने यह भी कहा कि गृह मंत्री के रूप में वे चुनाव करवाने की बात स्वयं सदन में कह चुके हैं। विपक्ष ने कहा है कि इस निर्णय के बावजूद वो मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में 42 हज़ार लोग मारे गए हैं क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और इसके कारण वहां आतंकवाद खड़ा होता था। जब समय ये सिद्ध कर दे कि किसी से कोई गलत फैसला हुआ है, तो देशहित में उसे वापस आना चाहिए और इसके लिए अभी भी समय है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कमज़ोर और वंचित वर्ग किसी भी नागरिक के सम्मान को चोट पहुंचाने वाला नाम है। इस कानून में कमज़ोर और वंचित की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग नाम जोड़ने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की शुरूआत 1989 में हुई और बाद में यह चरम पर पहुंचा। इसके कारण हज़ारों विस्थापित हुए लोग, विशेषकर कश्मीरी पंडित और सिख, देशभर में बिखर गए और अपने ही देश में निराश्रय हो गए। इन विस्थापित कश्मीरियों को गले लगाने का काम पूरे देश ने किया। श्री शाह ने कहा कि 46,631 परिवार कश्मीर से विस्थापित हुए और मोदी सरकार के कई प्रयासों से अब तक 1 लाख 57 हज़ार 967 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। उन्होने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार विस्थापितों को न्याय देने के प्रति कटिबद्ध है, ऐसे लोग मतदान भी कर सकेंगे, चुनाव भी लड़ सकेंगे और जम्मू और कश्मीर में मंत्री भी बन सकेंगे।

हमारी सेना जीत रही थी, और दुश्मन सेना पीछे हट रही थी उस वक्त अगर नेहरु जी दो दिन और रुक जाते और सीजफायर नहीं करते तो आज पूरा कश्मीर हमारा होता

श्री अमित शाह ने कहा कि 1947 में 31,779 परिवार पाक–अधिकृत कश्मीर से जम्मू और कश्मीर में विस्थापित हुए और इनमें से 26,319 परिवार जम्मू और कश्मीर में और 5,460 परिवार देशभर के अन्य हिस्सों में रहने लगे। 1965 और 1971 में हुए युद्धों के बाद 10,065 परिवार विस्थापित हुए और कुल मिलाकर 41,844 परिवार विस्थापित हुए। इन विधेयकों के माध्यम से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों और 1 सीट पाक–अधिकृत कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए नामांकित करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने संवेदना के साथ किया है। श्री शाह ने कहा कि पहले जम्मू में 37 सीटें थीं जो अब 43 हो गई हैं, कश्मीर में पहले 46 सीटें थीं वो अब 47 हो गई हैं और पाक–अधिकृत कश्मीर की 24 सीटें रिज़र्व रखी गई हैं, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। जम्मू और कश्मीर के इतिहास में पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं और अनुसूचित जाति के लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया है। जब भी युद्ध हुआ और आतंकवादियों ने हमला किया तब हमेशा हमारे गुर्जर–बकरवाल भाइयों ने देश के तिरंगे को ऊंचा किया और आज सालों बाद उन्हें न्याय मिलने जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को तीन परिवार रोक कर बैठे थे, जो धारा 370 को एन्जॉय कर रहे थे। उन्होने कहा कि गुर्जर भाइयों की एक भी सीट लिए बिना बहुत संवेदनशीलता के साथ बकरवाल भाइयों को सभी लाभ

दिए जाएंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि जहां तक देश की एक भी इंच ज़मीन का सवाल है, मोदी सरकार का नज़रिया तंग है और रहेगा और हम इसके लिए दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को यह अधिकार नहीं है कि बड़ा दिल दिखाने के लिए देश का भूभाग चले जाने पर मूक दर्शक बन कर बैठे रहें। गृह मंत्री ने कहा कि जो आजादी के बाद के भारत की रचना को जानते हैं, उन्हें मालूम होगा कि हैदराबाद में कश्मीर से भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन क्या जवाहरलाल नेहरू गए वहाँ थे या फिर जूनागढ़, लक्षद्वीप या जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ एक ही जगह जम्मू–कश्मीर का काम देखा था और उसे भी वे आधा छोड़कर आ गए। 550 से ज्यादा रियासतों का भारत में विलय हुआ, कहीं भी धारा 370 नहीं लगी, सिर्फ जम्मू–कश्मीर नेहरू जी देख रहे थे, तो वहीं क्यों लगी? कश्मीर में विलय में हुई देरी के बारे में श्री शाह ने कहा कि महाराजा पर शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था और इसी कारण विलय में देर हुई और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिला। गृह मंत्री ने विपक्ष से सवाल किया कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हुआ, लेकिन कहीं पर भी धारा 370 क्यों नहीं है। श्री शाह ने कहा कि न तो जूनागढ़, जोधपुर, हैदराबाद और न ही लक्षद्वीप में धारा 370 है। धारा 370 की शर्त किसने रखी और सेना भेजने में देरी क्यों हुई, विपक्ष को इसका जवाब जनता को देना होगा।

गृह मंत्री ने कहा कि यह सर्वविदित है कि अगर असमय सीजफायर नहीं होता तो पाक अधिकृत कश्मीर नहीं होता। अगर उस समय दो दिन और रुक गये होते तो पूरा पाक अधिकृत कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। श्री शाह ने कहा कि एक तो कश्मीर का मामला यूएन में ले ही नहीं जाना चाहिए था और अगर ले भी जाया गया तो इस मामले को अनुच्छेद 51 में क्यों ले गए। उन्होने कहा कि अगर इस मसले को अनुच्छेद 35 में ले गए होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। गृह मंत्री ने अगर दो दशक बाद भी ऐसा लगेगा कि धारा 370 को हटाने का फैसला गलत है तो हम स्वीकार करेंगे कि यह हमारा और हमारी सरकार का फैसला है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला लिया है और न ही मोदी जी इस फैसले से पीछे सकते हैं, न ही कैबिनेट और पार्टी इससे पीछे हट सकती है। अहम फैसलों की जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ती है।

श्री अमित शाह ने कहा कि पूरा कश्मीर और कश्मीर जाने वाले दो करोड़ पर्यटक, लाखों अमरनाथ यात्री और वैष्णो देवी के दर्शन करके आए श्रद्धालु सभी एक स्वर में कहते हैं कि कश्मीर की स्थिति अच्छी है। श्री शाह ने कहा कि कश्मीर में 40 हजार से अधिक लोग मारे गए, कई पिता अपने कंधे पर बेटे के जनाजे लेकर गए, कई लोग अपनी बेटी की डोली तक नहीं देख पाए और कई बहनों ने अपने भाई को खो दिया। संवेदनशील हृदय वाले लोग ही उनकी वेदना महसूस कर सकते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने और धारा 370 समाप्त होने के बाद आज कश्मीर के युवाओं का भविष्य ब्लैक नहीं है, बल्कि स्कूल का ब्लैक बोर्ड उनका भविष्य बन गया है। जो युवा पत्थर लेकर घूमते थे, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उनके हाथों में लैपटॉप थमाने का काम किया है। कश्मीर में यह बदलाव हुआ है कि धारा 370 को आधार बनाकर आतंकवाद और अलगाव की बात करने वाले लोगों को अब कश्मीर की जनता अनसुना कर डेमोक्रेसी एवं डेवलपमेंट की बात करती है।

गृह मंत्री ने सदन को बताया कि धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में अलगाववाद की भावना समाप्त हो जाएगी और जब अलगाववाद की भावना समाप्त होगी तो धीरे धीरे आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। विपक्ष को ऐसा लगता है कि पिछले 40 चालीस साल की उनकी गलतियां मोदी जी 4 साल में सुधार देंगे। गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 तक कश्मीर में कुल 7217 आतंकवादी घटनाएं हुई थीं, लेकिन 2014 से अब तक पिछले लगभग 10 साल में सिर्फ 2197 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। आतंकवादी घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी हुई है जबकि धारा 370 हटाने को अभी चार साल ही बीते हैं। वर्ष 2004 से 2014 तक कश्मीर में कुल 2829 सुरक्षा कर्मी और नागरिक मारे गए, जबकि 2014 से 2023 तक 891 सुरक्षा कर्मी और नागरिक मारे गए जो पहले की तुलना में 70 फीसदी कम है। सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में भी 50 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2010 में संगठित पत्थरबाजी की 2654 घटनाएं हुई जबकि 2023 में धारा 370 हटाने के सिर्फ चार साल बाद एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई। वर्ष 2010 में पत्थरबाजी में 112 नागरिक मारे गए थे जबकि 2023 में पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं हुई, इसलिए किसी की मृत्यु का सवाल ही नहीं है। वर्ष 2010 में पत्थरबाजी के कारण घाटी के 6235 नागरिक जख्मी हुए थे, लेकिन 2023 में यह आंकड़ा शून्य है। श्री शाह ने कहा कि 2010 में सीजफायर उल्लंघन की घटनाएं 70 थीं जो 2023 में सिर्फ 6 हैं। 2010 में घुसपैठ के प्रयास 489 बार हुए जबकि इस साल अब तक सिर्फ 48 हुए हैं। वर्ष 2010 में घाटी छोड़कर भागे आतंकवादियों की संख्या 18 थी, जबकि 2023 में यह संख्या 281 है।

हमने सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, बल्कि आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने का काम किया है। साथ ही आतंकवाद को फाइनांस करने

वालों पर भी कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में NIA ने टेरर फाइनांस के 32 केस दर्ज किए, जबकि 2014 से पहले एक भी केस दर्ज नहीं किया गया था। स्टेट इनवेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फाइनांस के 51 केस दर्ज किए जबकि पहले स्टेट इनवेस्टिगेशन एजेंसी की जरूरत ही महसूस नहीं की गई। टेरर फाइनांस के मामलों में अब तक 229 गिरफ़्तारी हुई, 150 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई, 57 प्रॉपर्टी सीज की गई है। इसके अलावा NIA ने 134 बैंक खातों में लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की रकम को फ्रीज करने का काम किया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले कश्मीर में आतंकवादियों के जनाजों में 25–25 हजार लोगों की भीड़ जमा होती थी लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद ऐसे दृश्य दिखना बंद हो गए। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमने निर्णय किया कि किसी भी आतंकवादी के मारे जाने के बाद संपूर्ण धार्मिक रीति–रिवाज के साथ घटनास्थल पर ही उसे दफना दिया जाएगा। पत्थरबाजी की घटनाएं भी बंद हुई क्योंकि सरकार ने तय किया है कि अगर किसी अभ्यर्थी के परिवार में पथरबाजी का केस है तो उसे सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी।

सरकार ने तय किया है कि अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि टेलीफोन रिकॉर्ड के आधार पर अगर साबित होता है कि किसी के परिवार का कोई व्यक्ति आतंकवाद को बढ़ावा देने में लिप्त है तो उसे नौकरी से बर्खास्त करने के सर्विस रूल्स बनाए गए हैं।

जीरो टेरर प्लान और कंप्लीट एरिया डॉमिनेशन के माध्यम से पूरे आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित करने का काम किया गया है। जेल पहले अड्डे थे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने जेलों में जैमर लगाकर सख्ती करने का काम किया है। कश्मीर में 105 करोड़ रुपए की लागत से आतंकवादियों के लिए एक जेल बनाई जा रही है, जिसकी सुरक्षा कोई भेद नहीं पाएगा। आतंकवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाले बार काउंसिल के लोगों को भी संदेश दे दिया गया है और रोजगार, पासपोर्ट एवं सरकारी ठेकों के लिए हमने ढेर सारे कदम उठाए हैं।

हमारी सरकार के समय में भी आतंकवादी हमले हुए, उरी और पुलवामा में आतंकवादी घटनाएं हुईं, लेकिन हमने घर में घुसकर जवाब देने का काम किया। आतंकवादियों के लिए हमारे मन में कोई संवेदना नहीं है। आतंकवादी अगर हथियार डाल दें और मुख्यधारा में शामिल हो जाएं तो उनका स्वागत है। नॉर्थ ईस्ट में कई लोग हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे हैं। सरकार ने कश्मीर के युवाओं के लिए कई कदम उठाए हैं। धारा 370 और 35 ए कश्मीर के लोगों के साथ तो अन्याय करती ही थी, देश के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाती थी। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान के मसले पर सवाल उठाते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आंदोलन किया और उनकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। आज उन्हे खुशी है कि कश्मीर के लिए बलिदान देने वाले फौजी से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक हर व्यक्ति की आत्मा इस देश से दो प्रधान, दो विधान और दो निशान खत्म होने पर संतोष की सांस ले रही होगी।

धारा 370 पर आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है और 130 करोड़ जनता की ओर से वे इस फैसले का स्वागत करते हैं। आज एक संविधान, एक राष्ट्रीपय ध्वाज और एक प्रधानमंत्री बन चुका है और अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो चुका है। पहले कश्मीर में दो राजधानी और दो दरबार थे और सालाना 200 करोड़ रुपए का खर्च होता था जबकि अब एक केंद्रीय कानून है जो पूरे देश की तरह कश्मीर पर भी लागू होता है। कश्मीरी, डोगरी और हिन्दी को मान्यता देने का काम पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। 35 ए के तहत कश्मीर की महिलाओं को न्याय देने, शिक्षा या नौकरी में रिजर्वेशन देने, पहली बार एसटी समुदाय को विधानसभा में आरक्षण देने, कश्मीर में शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने, भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वसन में उचित मुआवजा देने का कानून, वन अधिकार कानून लागू कराने, एससी–एसटी उत्पीड़न रोकथाम कानून लागू करने और व्हिसलब्लोअर संरक्षण कानून लागू कराने का काम पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

आज एक संविधान, एक राष्ट्रीय ध्वाज और एक प्रधानमंत्री बन चुका है और अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो चुका है।

लाल चौक पर 26 जनवरी को घरकृघर तिरंगा फहराया गया। 30 साल से कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे लेकिन अब तीन थिएटर चालू हो चुके हैं। पिछले तीन सालों में कश्मीर में 100 फिल्मों की शूटिंग हुई है। देश की जनता अब समझ गई है कि कश्मीर के सवाल के मूल में जवाहरलाल नेहरू जी की गलतियां थीं।

प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से इस देश को वादा किया था कि कश्मीर के युवाओं को हाथ में कभी बंदूक और पत्थर नहीं लेने पड़ेंगे। उनके हाथों में लैपटॉप और किताबें होंगी और अब आतंकवाद मुक्त नया कश्मीर बनने की शुरुआत हो चुकी है। उन्होने कहा कि जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो कश्मीर देश के सभी राज्यों के समकक्ष होगा और दुनिया भर के यात्री कश्मीर आएंगे।

सुशासन से उत्तर प्रदेश का विकास

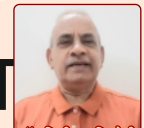

डॉ0 दिलीप अग्निहोत्री

वर्तमान सरकार ने लोक कल्याण की सर्वाधिक योजनाए बनाने के साथ उनका शतप्रतिशत क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही उद्देश्य है। निरंतर प्रगति पर है। इसमें जितनी योजनाओं को शामिल किया गया है, उनमें प्रायः सभी में यूपी नंबर वन है। पिछले दिनों काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया था। करोडों लोगों का जीवन इन कल्याणकारी योजनाओं से बदल गया है। लाभार्थी अपना अनुभव बताते हुए भावुक हो जाते है। उन्होंने जिन सुविधाओं की अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी, वह सहज ही उन्हें उपलब्ध हुई हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में उन लोगों को विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है जो किसी कारण से योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए थे।

विकसित भारत संकल्प यात्रा में सहभागी हुए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये। प्रधानमंत्री आवास योजना,स्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियां से संवाद किया. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के माध्यम से जिन लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिला है, उनके साथ संवाद और जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उनका रजिस्ट्रेशन करके, उन्हें भी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। इस यात्रा से प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय, हर घर गरीब परिवार को उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन, हर घर में एलईडी बल्ब के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ–साथ सस्ती बिजली उपलब्ध कराने, आयुष्मान भारत योजना, हर घर नल योजना,मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ आदि अनेक कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ा गया है। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा यात्रा पच्चीस जनवरी तक लगभग ढाई लाख पंचायतों में पच्चीस हजार वीडियो वैन के माध्यम से पहुंचेगी। यह उत्तर प्रदेश के सत्तावन हजार स्थानां पर, लगभग सात सौ से अधिक नगर निकायों में पहुंचेगी.विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लाभार्थियों की जुबानी उनकी कहानी सुनने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने गांवां मे गरीबों, पिछड़ों, शोषितों व महिलाओं को संबल देने का कार्य किया है। आज नौ करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन मिल गया है। यदि अभी भी कोई बहन इससे वंचित रह गयी है, तो उसे गैस कनेक्शन देने का कार्य किया जायेगा। पचपन करोड़ लोग जनधन खाता खुलवाकर बैंक की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत करीब बारह करोड़ किसानों के खाते में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंचाये गये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत चार करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ

देकर नई ताकत दी गयी है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत साढ़े बारह करोड़ इज्जत घर देने का कार्य किया है। आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत करीब ग्यारह करोड़ परिवारों के पचास करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया है, जिससे गंभीर बीमारियों में पांच लाख रुपये का इलाज हो सकता है।

जिन लोगां को योजनाओं का लाभ मिला है या जिसमें कोई कमी रह गयी है, तो उसकी जानकारी हासिल करना और जिन लोगां को अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' प्रारम्भ हुई है।

केन्द्र सरकार की योजनाएं गांव को मजबूती प्रदान कर रही हैं, गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण व युवाओं को आवाज दे रही है तथा किसानां को सहजतापूर्वक हर क्षेत्र में बढ़ने का मौका दे रही है। जो भी लाभार्थी यहां चर्चा कर रहे थे, वह भावुक हो रहे थे। भारत की अर्थव्यवस्था पांचवें नम्बर पर आ गयी है, जो पहले ग्यारहवें नम्बर पर थी। साढ़े तेरह करोड़ परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ गये हैं। नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस–वे, मेडिकल कॉलेज, एम्स आदि का निर्माण कराया गया है। गुणवत्तापूर्ण दवा का एक्सपोर्ट करीब डेढ़ सौ प्रतिशत तथा पेट्रो केमिकल्स का एक्सपोर्ट एक सौ छह प्रतिशत बढ़ा है। रक्षा क्षेत्र में प्रयोग होने वाले सामानों का उत्पादन भारत स्वयं कर रहा है। तीन वर्षां में पांच लाख से अधिक बुलेटप्रूफ जैकेट भारतीय सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध करायी गयी हैं। इनका विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। भारत में राफेल का बेड़ा आया है। देश में ही पनडुब्बी एवं लड़ाकू जहाज बनाये जा रहे हैं। विगत साढ़े नौ वर्षों के दौरान देश में खेलों के प्रति जबर्दस्त जागरुकता आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेलों इंडिया फिट इण्डिया मूवमेंट, सांसद खेल प्रतियोगिता अभियान सार्थक हुए है। इस अभियान में उत्तर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक उल्लेखनीय है।

योगी आदित्यनाथ ने इस ओर गंभीरता से प्रयास किया. उन्होंने कहा कि यूपी के हर गांव में ओपेन जिम के साथ खेल का मैदान, सभी विकासखण्डों में मिनी स्टेडियम तथा प्रत्येक जनपद में स्टेडियम बनाने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में पैसठ हजार युवक मंगल दल व महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट्स उपलब्ध कराने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। एक जनपद एक खेल योजना के अन्तर्गत प्रत्येक खेल के लिए एक प्रशिक्षक तैनात किया जा रहा है। भारत सरकार की तर्ज पर खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत खेल संसाधनों को बढ़ाया जायेगा। एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की गयी है। प्रदेश सरकार ने अब तक पांच खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनपद बस्ती में सांसद खेल महाकुम्भ के तीसरे संस्करण का शुभारम्भ किया। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सांसद खेल महाकुम्भ के पहले साल एक लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अब तीसरे साल साढ़े तीन लाख खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। विगत नौ वर्षां में आयोजित हुए ओलम्पिक खेलों, एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गये पदकों की संख्या में वृद्धि हुयी है। विश्वस्तरीय गुणवत्ता वाले संसाधनों की उपलब्धता करायी गयी।भारत सरकार द्वारा खिलाडियों के लिए पचास हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेन्ड की व्यवस्था की गयी है। विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण देने के लिए आठ हजार कोच की व्यवस्था की गयी, जिसमें पांच हजार पुरूष तथा तीन हजार महिलाएं हैं। चौतीस कोचिंग सेण्टर बनाये गये। खेलो इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत ढाई हजार खिलाड़ियों के लिए एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। आठ सौ से अधिक खेल सेण्टर बनाये गये, जिसमें से अस्सी उत्तर प्रदेश में हैं। स्किल इण्डिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भारत को मजबूती प्रदान कर रही हैं।

विकसित भारत, अटल सुशासन

श्री अर्जुन राम मेघवाल

सुशासन भारत की प्राचीन संस्कृति और लोकाचार की विरासत है। बौद्ध धर्म के गण संघ, भगवान बसवेश्वर द्वारा स्थापित 11वीं शताब्दी के अनुभव मंडप, चाणक्य के अर्थशास्त्र, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान नागरिक योजना, मौर्य सम्राट अशोक की विरासत आदि के माध्यम से प्राप्त लोकतांत्रिक मूल्य विरासत में मिले ज्ञान हैं जो बेहतर शासन को सक्षम बनाते हैं। . सुशासन दिवस के अवसर पर, जो पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, स्वतंत्र भारत में प्रचलित उत्कृष्ट शासन उपायों को संस्थागत बनाने में उनकी उल्लेखनीय भूमिका पर प्रकाश डालना अनिवार्य है।

स्वतंत्रता के बाद, सुशासन शासन सुधारों का केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन केवल चर्चाओं में। यह संविधान सभा की बहसों और योजना आयोग जैसे संस्थानों द्वारा तैयार किए गए नीति पत्रों में शामिल था, लेकिन विचार खराब कार्यान्वयन रिकॉर्ड के साथ कागज पर ही रह गए। वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व में स्थिति बदल गई और शासन में सुधार के प्रयास जनता के जीवन में प्रतिबिंबित होने लगे।

वाजपेयी का संसद में लंबा कार्यकाल रहा – उन्होंने लोकसभा सांसद के रूप में 10 बार और राज्यसभा में दो बार सांसद के रूप में कार्य किया। उन्होंने इस मंच का उपयोग सुशासन पर प्रकाश डालने के लिए किया। विपक्ष के सदस्य के रूप में, उनके तर्कपूर्ण तर्क और रचनात्मक आलोचना में बहुत गंभीरता थी और उन्होंने एक कल्याण–केंद्रित शासन प्रणाली के निर्माण को प्रेरित किया। प्रधान मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उभरी जन–केंद्रित पहल भारत की परिवर्तनकारी यात्रा में मील का पत्थर बन गईं। किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज, नदियों को आपस में जोड़ना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, आदिवासी मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय जैसी योजनाओं और विचारों ने समाज के हर वर्ग को छुआ। अर्ध–न्यायिक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की गई और बिजली क्षेत्र में नियामक ढांचे में सुधार के लिए बिजली अधिनियम में संशोधन किया गया। मई 1998 में परमाणु परीक्षणों ने भारत को परमाणु शक्ति बना दिया। जटिल कश्मीर समस्या के समाधान के लिए प्रसिद्ध वाजपेयी सिद्धांत "इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत" (मानवता, शांति और कश्मीरी लोगों की पवित्रता) के लोकप्रिय ज्ञान को प्रतिध्वनित करता है।

उनके प्रसिद्ध शब्द, "आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं", आज भी भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शन करते हैं। वाजपेयी सरकार ने शहीदों के शवों को उनके घर तक लाने की अनुमति दी थी ताकि लोग देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों का सम्मान कर सकें। वह सर्वसम्मति और व्यावहारिकता के व्यक्ति थे, जिसने 2000 में शांतिपूर्ण तरीके से तीन नए राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन संभव बनाया।

वाजपेयी बीआर अंबेडकर के विचारों की भविष्यवादी

अंतर्दृष्टि और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका से बहुत प्रभावित थे। यह वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के आग्रह पर था कि भाजपा समर्थित वीपी सिंह सरकार ने 31 मार्च, 1990 को अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया। 26 अलीपुर रोड, दिल्ली, जहां सिरोही, राजस्थान के महाराजा थे, को विकसित करने की वाजपेयी की इच्छा थी 1951 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद अंबेडकर को रहने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप परिसर को एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया जो लोगों को सामाजिक समानता की आकांक्षा के लिए प्रेरित करेगा। शहरी विकास मंत्रालय ने 14 अक्टूबर 2003 को वाजपेयी की देखरेख में इस निजी संपत्ति के विनिमय विलेख पर हस्ताक्षर किए और दिसंबर 2003 में विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। यूपीए शासन ने इस परियोजना को स्थगित रखा। बाद में मोदी सरकार ने इसे 100 करोड़ रुपये की लागत से डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया और 13 अप्रैल, 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया।

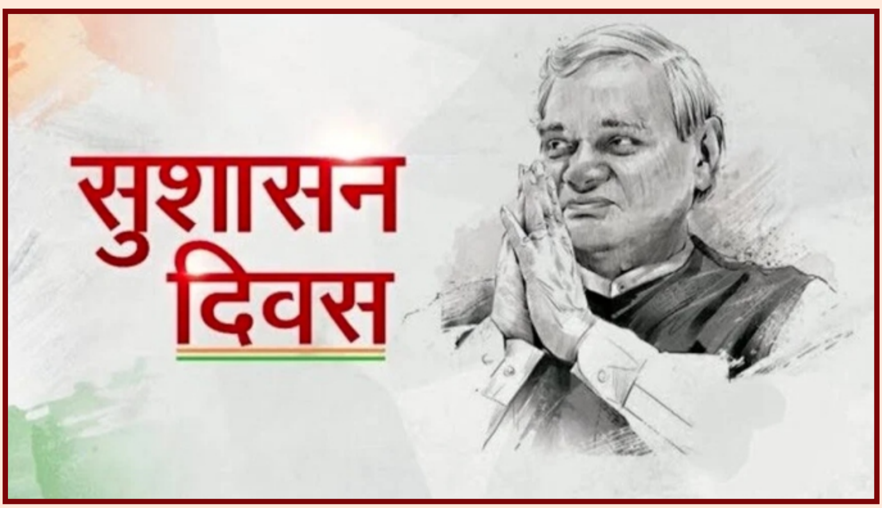

21वीं सदी की शुरुआत में वाजपेयी ने कई पहल करके सुशासन की बात कही। पीएम मोदी ने अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए इन उपायों की गति और पैमाने को बढ़ा दिया है। डीबीटी और जेएएम जैसे तकनीकी हस्तक्षेपों ने संस्थानों में लोगों का विश्वास मजबूत किया है। भारतमाला, सागरमाला, राष्ट्रीय संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन, कृषि अवसंरचना निधि आदि के माध्यम से बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा दिया गया है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से जम्मू और कश्मीर में सेवाओं की आपूर्ति में सुधार हुआ है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है।

"न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के मंत्र ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने में सुधार किया है। पीएम गतिशक्ति, प्रगति, मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्षमता निर्माण, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यवसायों, व्यक्तियों और अन्य हितधारकों पर अनुपालन बोझ को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने जैसी पहलों के साथ विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से शासन के दायरे को तोड़ने से सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित हो रही है। . जीएसटी, श्रम संहिता, दिवाला और दिवालियापन संहिता, नई शिक्षा नीति, मुद्रा, पीएम आवास योजनाएं, पीएम किसान का कार्यान्वयन और कर विवादों का निर्बाध समाधान ऐसी पहल हैं जिन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के अन्य आयामों को मजबूत किया है। भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 2015 में 145 से बढ़कर 2020 में 63 हो गई है। इसी तरह, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 81 (2015) से बढ़कर 46 (2021) हो गई है।

प्रधान मंत्री ने राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में एक साथ चुनाव कराने, एक ही मतदाता सूची, न्यायिक सुधार आदि का आह्वान किया है।

सुशासन संवैधानिक ढांचे के भीतर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करके उनकी सेवा करने का एक साधन है। अटलजी की दूरदर्शिता, नेतृत्व, मार्गदर्शन और अमूल्य अंतर्दृष्टि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जैसा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव की पृष्ठभूमि में सुशासन दिवस मना रहा है, आइए हम आत्मनिरीक्षण करें और नए भारत के निर्माण के लिए "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" की भावना से कार्य करने का संकल्प लें।

भारतीय दर्शन की अनोखी खोज

श्री हृदयनारायण दीक्षित

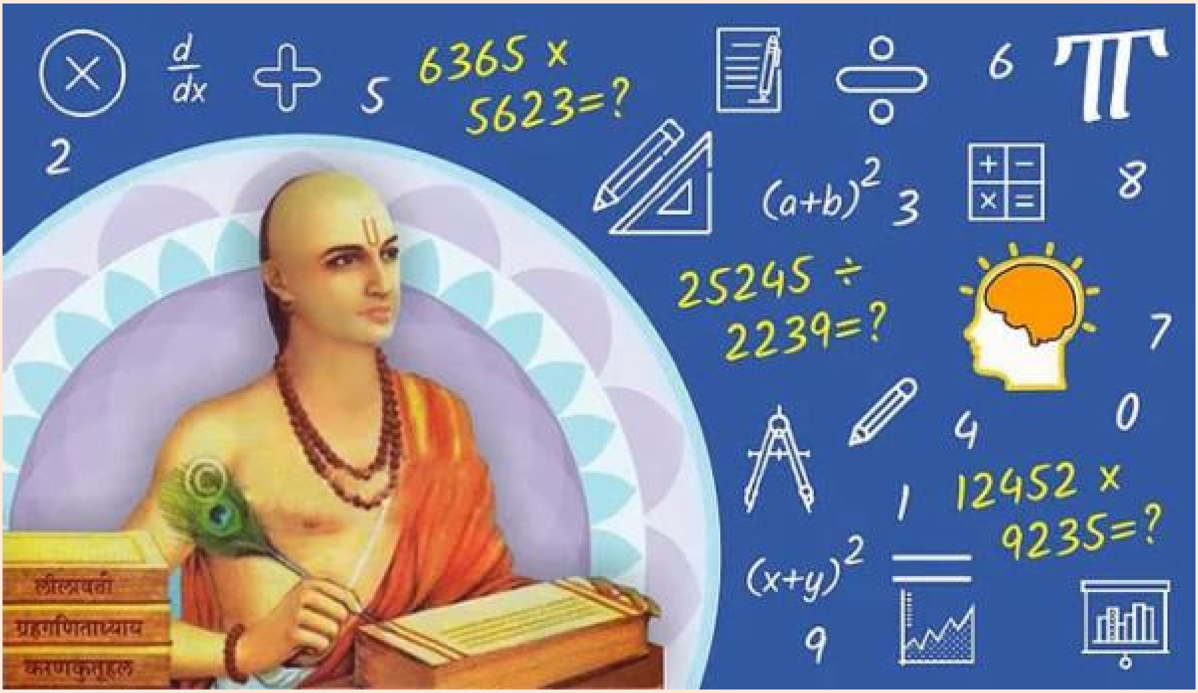

अस्तित्व में दो नहीं। यहाँ द्वैत नहीं है। वेदांत अनुभूति में इसे अद्वैत कहा गया। ऋग्वेद के एक ऋषि ने इसे 'पुरुष' कहा और बताया कि जो भूतकाल में अब तक हो चुका और जो आगे होगा वह सब पुरुष ही है। पुरुष एक है। इसी के भीतर सम्पूर्णता है। यही बात ऋग्वेद में 'अदिति' के लिए कही गई है और छान्दोग्य उपनिषद में 'भूमा' के लिए। भूमा सम्पूर्णता का पर्याय है। पूर्ण भारतीय दर्शन की अनोखी खोज है। 'पूर्ण' असीम विराट है। संख्या गणित का विषय है। विराट अस्तित्व के रहस्य गणित की पकड़ में नहीं आते। गणित में बड़ी से बड़ी संख्या भी पूर्ण का ही भाग होती है। कोई भी संख्या पूर्ण से बड़ी नहीं होती। 'पूर्ण' वैदिक पूर्वजों का आत्मीय विषय रहा है। 'शतपथ ब्राह्मण' उत्तर वैदिक काल का प्रमुख सामाजिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक व दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें संख्या व गणित के तमाम उल्लेख हैं लेकिन इसी के अंश वृहदारण्यक उपनिषद (पांचवें अध्याय) में पूर्ण की रम्य व्याख्या है। बताते हैं–'वह पूर्ण है, यह पूर्ण है–'पूर्णमदः पूर्णमिदं'। मन प्रश्न करता है कि क्या पूर्ण भी दो हो सकते हैं। एक यह पूर्ण और दूसरा वह पूर्ण। इस जिज्ञासा का उत्तर भी इसी मंत्र में है–''यह पूर्ण उस पूर्ण का ही विस्तार है–पूर्णात पूर्णमुदच्यते।'' शंका तो भी शेष न रहे इसलिए आगे कहते हैं–''पूर्ण में पूर्ण निकाल देने पर भी पूर्ण ही बचता है–पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।'' भारतीय अनुभूति का यह पूर्ण उल्लासदायी है।

प्रगाढ़ अनुभूति और दर्शन में 'पूर्ण' पूरा पूर्ण है। हम सबको अनेक पूर्ण दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन उन्हें पूर्ण नहीं कहा जा सकता। जो वास्तविक पूर्ण है, उस पूर्ण में कुछ भी घटाओ, जोड़ो, गुणा करो, पूर्ण पूर्ण ही रहता है। निस्संदेह गणित में कोई भी अंश या संख्या पूर्ण से छोटी होती है लेकिन पूर्ण अनुभूति में अंश या संख्या भी पूर्ण ही होती है। सारी संख्याएं पूर्ण का ही अविभाज्य अंश हैं और अंश कभी पूर्ण से पृथक अस्तित्व नहीं रखते। इस दृष्टि से हम सब पूर्ण हैं। पूर्णता के बोध के अभाव में अपूर्ण जान पड़ते हैं। अपूर्ण होना दुख है, पूर्ण होना आनंद। वेदों में अनेक देवों की स्तुतियां हैं। पश्चिमी विद्वान इसी आधार पर भारतवासियों को बहुदेववादी बताते हैं। हम भारतवासी बहुदेववादी नहीं, बहुदेव उपासक हैं। ऋषि

की घोषणा है कि इन्द्र, अग्नि तमाम देवता हैं लेकिन सत्य एक है, विद्वान उसे भिन्न भिन्न ढंग से बताते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं–''वह पुरुष और आदित्य में एक ही है।'' संभवतः कुछ विद्वान पुरुष को और कुछ सूर्य को अलग अलग बताते रहे होंगे। ऋषि दोनों को एक बताते हैं। पूर्णता सनातन प्यास है। हम सब अपूर्ण हैं। भोजन या पानी की प्यास अपूर्णता का संदेश है। सांसारिक उपलब्धियों की इच्छा भी हमारी अपूर्णता की ही सूचना है। इच्छा, अभिलाषा या आकांक्षा अपूर्णता के ही बोधक हैं। तनावग्रस्त होने का कारण भी हमारी अपूर्णता है। हम अतृप्त हैं। हम किसी भी मार्ग या उपाय से समृद्धि चाहते हैं और समृद्धि अतिशीघ्र नई रिक्तता में बदल जाती है। सुख फिसल जाता है, दुख घेर लेता है। प्रकृति सृष्टि सम्पूर्णता है। सम्पूर्णता में ही रहती है। सम्पूर्णता में ही प्रकट होती है। यहाँ सामान्य गणित नहीं है। पूर्ण से पूर्ण घटा देने पर शून्य नहीं बचता। यहाँ अस्तित्व की सम्पूर्णता का सुन्दर विवेचन है–''मेरा मन ऐसा ही मंत्र गढ़ने को उतावला है–मैं अपूर्ण हूँ। हम सब अपूर्ण हैं। मैं में हम घटाओ तो अपूर्ण मैं ही बचता है।'' मैं दुख है, हम होना सुख है और सम्पूर्ण होना आनंद। सम्पूर्णता की प्यास स्वाभाविक ही गहरी ही होनी चाहिए।

हम बोधरहित हैं सो अपूर्ण हैं। अपूर्ण हैं सो सांसारिक उपलब्धियों में पूर्णता खोजते हैं। सांसारिक उपलब्धियां क्षणभंगुर हैं। वे अपूर्ण से भी लघुतम हैं। हमारी अपूर्णता हमको बार–बार जगाती है। हम तनावग्रस्त होते हैं। अपूर्णता का ज्ञान अच्छा है। तब हम पूर्णत्व के बारे में विचार करते हैं। पूर्णता को प्राप्य मानते हैं। पूर्वजों ने शब्द संकेतों से ऐसा मार्ग दर्शन किया है। संसार के साथ स्वयं का ज्ञान ही पूर्णता की दिशा तय करता है।

कार्य और कारण की श्रंखला में पूर्ण विराम की गुंजाइश नहीं। 'ब्रह्म' पूर्णतम पूर्णता है। यह 'ब्रह्म' ही कारण है और 'ब्रह्म' ही कार्य। गीता के एक सुन्दर श्लोक (4.24) में 'ब्रह्म' ही 'ब्रह्म' को हवि अर्पण करता है–ब्रह्मार्पण ब्रह्म। 'ब्रह्म' ही अग्नि है और 'ब्रह्म' ही हवि। यह हवि 'ब्रह्म' को ही मिलती है। इसका परिणाम भी 'ब्रह्म' ही होता है। इसके पहले के श्लोक में ऐसा जानने वाले व्यक्ति के लिए ''ज्ञानावस्थित चेतसः–ज्ञान में स्थिर चेतना'' शब्द आए हैं। ऐसे व्यक्ति के सभी कर्म ''समग्रं विलीयते–सम्पूर्णता में विलीन होते हैं।'' लेकिन यह ज्ञान की उच्चतर स्थिति है। संसार का अध्ययन कार्य कारण की श्रंखला के विवेचन से होता है। संसार की प्रत्येक घटना के कारण होते हैं। ऐसे कारण के भी कारण होते हैं। कार्य कारण के प्रत्यक्ष सम्बंधों का अवसान सम्पूर्णता के बोध में ही होता है। हम संसार जानना चाहते हैं। इसलिए संसार विषय का ज्ञेय हुआ। जानकारी मिली यह ज्ञान हुआ। हमने जाना सो हम ज्ञाता हुए। लेकिन ज्ञाता और ज्ञान का सम्बंध भी अंत में समाप्त होता है। बोध के अंत में ज्ञाता नहीं बचता। ज्ञाता भी ज्ञान हो जाता है। ज्ञान भी अंतिम अवस्था में कहां बचता है? ज्ञाता, विषय, ज्ञान आदि सभी विभाजन सम्पूर्णता के ही भाग हैं। सम्पूर्णता का बोध भारतीय चिन्तन की अनूठी उपलब्धि है।

सत्य आधा नहीं होता। मित्रगण चर्चा में कहते हैं कि आपकी या हमारी बात 50 प्रतिशत सत्य है। कोई भी वचन प्रतिशत में सत्य नहीं होता। सत्य पूर्ण होता है। पूर्णता ही सत्य है और सत्य पूर्णता है। सत्य इससे कम नहीं होता। तैत्तिरीय उपनिषद में सत्यानुभूति की प्राप्ति के बाद का एक सुन्दर मंत्र है। मंत्र क्या खूबसूरत कविता है। ऋषि गाते हैं–''मैं अन्न हूँ। मैं अन्न हूँ। मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ। मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ।'' यहाँ अनुभूति का उल्लास है। इसलिए अभिव्यक्ति में दोहराव है। ध्यान देने योग्य बात है कि मैं स्वयं अन्न और मैं ही अन्न का भोक्ता। आगे कहते हैं–''मैं ही इन दोनों अन्न और अन्न के भोक्ता का संयोग कराता हूँ–अहम् श्लोककृत।'' फिर कहते हैं–''मैं ही ऋत सत्य हूँ। प्रथम उत्पन्न हिरण्यगर्भ हूँ। देवों से पहले हूँ। अमृत की नाभि हूँ–अमृतस्य नाभिः।'' पूर्ण में ही अन्न, अन्न का उपभोक्ता, ऋत सत्य सहित सम्पूर्ण अस्तित्व विद्यमान है। यही अनुगूंज गीता में भी है। कृष्ण कहते हैं–मैं सूर्य हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, आदि। पूर्वज पूर्ण में रहते थे। पूर्ण विराट है। उसकी असंख्य अभिव्यक्तियाँ हैं। हम उनकी गणना करने का प्रयास करते हैं। व्यावहारिक जगत् में ऐसा अनुचित भी नहीं है लेकिन पूर्ण का गणित नहीं होता। पूर्ण के भीतर ही गणित और अगणित है। व्याख्येय और अव्याख्येय भी हैं।

जम्मू कश्मीर में विकास का नया सूर्योदय

श्री मृत्युंजय दीक्षित

भारत की संप्रभुता और जम्मू कश्मीर प्रान्त के लिए 11 दिसंबर 2023 एक ऐतिहासिक दिन बनकर आया। इस दिन उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाने के निर्णय को वैध ठहराते हुए कहा कि यह एक अस्थाई धारा थी जिसे आज नहीं तो कल हटना ही था। मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। अदालत ने कहा कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है और अनुच्छेद– 370 को बेअसर करने से जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने कहा कि धारा 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है और केंद्र सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कई महत्वपूर्ण व ऐतिहासक टिप्पणियां की हैं जिनमे कहा गया है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद जम्मू कश्मीर के पास संप्रभुता का कोई तत्व नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के शासन के उद्देश्य के साथ उचित संबंध होना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जब संविधान सभा भंग कर दी गई तो सभा की केवल अस्थायी शक्ति समाप्त हो गई और राष्ट्रपति के आदेश पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा। राष्ट्रपति द्वारा सत्ता का उपयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं था और राज्य के साथ किसी सहमति की आवश्यकता नहीं थी। राष्ट्रपति द्वारा सत्ता का निरंतर प्रयोग दर्शाता है कि एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी और इस प्रकार से सीओ 273 अवैध है। जम्मू कश्मीर का संविधान क्रियाशील है और इसे निरर्थक घोषित कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जायेगा और हम लद्दाख को अलग करने के फैसले को बरकरार रखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अंत में कहा कि हम चुनाव आयोग को निर्देश करते हैं कि पुनर्गठन अधिनियम और राज्य के दर्जे 14 की धारा के अंतर्गत 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराये जायें।

न्यायालय ने एक यह व्यवस्था भी दी है कि राज्य में 1980 के बाद हुई सभी प्रकार की आतंकवादी /पलायन की घटनाओं की जांच के लिए एक कमेटी बनायी जाये जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात और कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय प्राप्ति का मार्ग खोलती है। इस व्यवस्था के आने के बाद 1980 के बाद घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ जो वारदातें हुई हैं उनकी जांच अब की जा सकेगी । उच्चतम न्यायालय की इस बेंच की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ कर रहे थे तथा बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे।

जस्टिस कौल की ऐतिहासिक टिप्पणी – जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर अपने फैसले में जस्टिस संजय किशन कौल ने कश्मीरी पंडितों के पलायन का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हाने 1980 से राज्य में हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए एक सत्य और सुलह आयोग

बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि यह आयोग आपराधिक जांच आयोग की तरह काम नहीं करेगा। जस्टिस कौल का मानना है कि आतंक के चलते राज्य की महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने बहुत कुछ झेला है।इसे भुलाकर आगे बढ़ने के लिए जख्मों को ठीक करने की जरूरत है। राज्य एवं राज्य से बाहर के तत्वों के द्वारा यहां के लोगों के विरुद्ध किये गये मानवाधिकारों के हनन की सामूहिक समझ विकसित करना ही मरहम लगाने की दिशा में पहला निष्पक्ष प्रयास होगा। आयोग के सहारे काफी हद तक उनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है।

5 अगस्त 2019 को गृहमंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 370 व 35 ए को हटाने से सम्बंधित विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य के परिवारवादी नेता फारुख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग व कई अन्य संगठन इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय पहुंच गये थे। उन सभी की याचिकाओं पर अगस्त से सितंबर माह के बीच 16 दिन चली सुनवाई के बाद यह ऐतिहासिक निर्णय आया है जिस पर पर सभी देशवासियों और राजनैतिक दलों सहित अलगाववादी नेताओं और पाकिस्तान की भी दृष्टि थी।

मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ वाली खंडपीठ के फैसले के बाद पाक परस्त अलगाववादी नेताओं व कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गयी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद –370 व 35– ए को हटाने का निर्णय वैध बताये जाने के बाद जहाँ एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के निर्णय को अब संवैधानिक मान्यता मिल गयी है वहीं दूसरी और कांग्रेस सहित उस संपूर्ण विपक्ष की राजनीति को बहुत गहरा आघात लगा है जो राष्ट्रीय संप्रभुता के इस विषय को भी तुष्टिकरण की राजनीति के चश्मे से देख रही थी।

अनुच्छेद 370 पर विपक्षी नेता और अलगाववादी जो अनर्गल प्रश्न उठा रहे रहे थे उन सभी प्रश्नों का उत्तर उच्चतम न्यायालय ने दे दिया है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब धारा 370 पर पूर्ण विराम लग चुका है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद अब जम्मू कश्मीर देश के अन्य राज्यों की तरह समान व्यवस्था वाला राज्य बन गया है। उच्चतम फैसला आ जाने के बाद जम्मू कश्मीर के गुपकार गठबंधन के नेताओं व अलगावादियों के होश उड़ गये हैं । जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन के सभी नेता जिस प्रकार अदालत के निर्णय को मानने से इनकार करते हुए जिस प्रकार एक लंबे संघर्ष की बात कर रहे हैं वह एक चिंतनीय विषय है। उच्चतम निर्णय पर पाकिस्तान से भी प्रतिक्रिया सामने आ गयी है और वहां पर खलबली मची है।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर लिखा कि अनुच्छेद –370 को निरस्त करने का निर्णय ऐतिहासिक है। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाईयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है। जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे प्रिय मानते हैं और संजोते हैं।केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित कई भाजपा नेताओं ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि यह निर्णय राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा। अनुच्छेद –370 के कारण जम्मू कश्मीर में वर्षों से अन्याय सह रहे लोगों को इस निर्णय से मुक्ति मिली है।

राज्य में विकास का नया सूर्योदय – अनुच्छेद –370 के रद्द किये जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में विकास की राह खुली है पर अब उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ जाने के बाद वहां विकास का नया सूर्योदय होने जा रहा है। वर्ष 2024 में कश्मीर घाटी तक ट्रेन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जम्मू कश्मीर में सड़कों, पुलों एवं सुरंगो के निर्माण से तस्वीर बदल रही है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर साल पहुंचने वाले एक करोड़ श्रद्धालुओं के लिए दिल्ली –अमृतसर– कटरा एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर राज्य भी तीव्र गति से डिजिटल हो रहा है और कई योजनाएं व सेवाएं ई– मोड पर उपलब्ध हो चुकी हैं। पर्यटन उद्योग को विकास के नये पंख लग रहे हैं जिसके अंतर्गत जनवरी– 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक राज्य में एक करोड़ 88 लाख 84 हजार 317 रिकार्ड पर्यटक आये । श्रीनगर की डल झील की रौनक वापस आ गयी है और फिल्मों की शूटिंग भी एक बार फिर प्रारंभ हो चुकी है।राज्य में औद्योगिक गतिविधियां की अब चल पढ़ी हैं जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या में भी कमी आ रही है। कुछ माह पूर्व हुई जी 20 की बैठक के माध्यम से पूरे विश्व ने एक नया कश्मीर देखा ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह की सधी हुई और ठोस रणनीति के कारण अब राज्य में आतंकवाद और अलगाववाद धीरे –धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर है।राज्य में पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं।कश्मीर में 2010 में पत्थरबाजी से 112 लोगों की मौत हुई थी जबकि 2023 में पत्थरबाजी से एक भी मौत नहीं हुई। अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अनुच्छेद –370 के कारण ही राज्य में अलगाववाद का जहर पनप रहा था वह मूल अब समाप्त हो चुका है किंतु राज्य की सुरक्षा के लिए वहां की जनसांख्यिकीय को भारत के पक्ष में करना ही होगा। अनुच्छेद– 370 के समापन के बाद राज्य में विकास का नया सूर्योदय होने जा रहा है जिसमें समाज के सभी वर्गों को न्याय मिलेगा।

विकसित भारत की कैसी होगी राह?

समावेशी विकास और मजबूत संस्थानों के बिना भारत को मध्यम आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत होने का जोखिम उठाना पड़ता है। भारत सरकार ने 2022 में खुद को 'विकसित भारत' (उन्नत भारत) बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में नई संसद के उद्‌घाटन के दौरान और नीति आयोग की ताजा बैठक में इसका उल्लेख फिर से किया। मैं इस लक्ष्य को लेकर खासा उत्साहित हूं क्योंकि मेरे सह–लेखक और मैंने अपनी पुस्तक 'अनशैकलिंग इंडिया: क्लियर चॉइसेज ऐंड हार्ड ट्रुथ्स फॉर इकनॉमिक रिवाइवल' में 'समृद्ध और समावेशी भारत' के समान दृष्टिकोण का सुझाव दिया है।

लेकिन 'विकसित भारत' बनने का क्या मतलब है? अर्थव्यवस्था का आकार कई कारणों से महत्त्वपूर्ण है लेकिन यह मानदंड अकेले ही विकसित देश का दर्जा पाने की पात्रता नहीं रखता है। उदाहरण के तौर पर चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसे एक महाशक्ति माना जाता है जो अंततः अमेरिका से आगे निकल जाएगा, लेकिन इसे विकसित नहीं माना जाता है क्योंकि इस देश के औसत नागरिक औसत अंग्रेजों की तुलना में चार गुना गरीब है और औसत अमेरिकी नागरिकों की तुलना में छह गुना गरीब हैं।

इसी तरह, भारत अब ब्रिटेन से आगे निकलकर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है लेकिन औसत भारतीय औसत अंग्रेजों की तुलना में 20 गुना गरीब हैं। ऐसे में हमें विकसित और प्रगतिशील देश वाले वाले मानदंड पर एक लंबी राह तय करनी है।

वर्ष 2022 में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 41 देशों को विकसित अर्थव्यवस्थाओं के तौर पर वर्गीकृत किया लेकिन इसकी परिभाषा स्पष्ट या समय के साथ सुसंगत नहीं दिखती है। विश्व बैंक 2022 की कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) के लिए 13,205 डॉलर की सीमा का उपयोग करते हुए लगभग 80 देशों को 'उच्च आय' वाली श्रेणी में वर्गीकृत करता है।

UNDP में मानव विकास सूचकांक (HDI) प्रति व्यक्ति GNI में मानव जीवन के अहम आयामों (जीवन प्रत्याशा, शिक्षा आदि) को जोड़ता है और यह 66 देशों को 'उच्च मानव विकास' श्रेणी में वर्गीकृत करता है जो एक विकसित अर्थव्यवस्था की मोटी परिभाषा के अनुरूप है।

यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि 2047 में एक विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होंगी, लेकिन विश्व बैंक और UNDP के पास विकसित अर्थव्यवस्था की परिभाषा के लिए स्पष्ट मानदंड हैं और आइए उनका उपयोग करके देखते हैं। मौजूदा स्तर पर विकसित देश के 13,205 डॉलर के प्रति

व्यक्ति GNI स्तर तक पहुंचने में प्रति व्यक्ति GNI में सालाना 7 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ भी 25 साल लगेंगे। इसका मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अगले 25 वर्षों तक GNI में प्रति वर्ष लगभग 8 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी होनी चाहिए। हाल के वर्षों में चीन को छोड़कर कुछ देशों ने यह वृद्धि निरंतर हासिल की है।

वर्ष 2021 में भारत का HDI स्कोर 0.633 था और 0.8 के उच्च मानव विकास की सीमा तक पहुंचने के लिए प्रति वर्ष लगभग 0.9 प्रतिशत की HDI वार्षिक वृद्धि की आवश्यकता होगी। वर्ष 1990 और 2021 के बीच HDI में भारत की वृद्धि लगभग 1.25 प्रतिशत सालाना थी।

लेकिन यह याद रखे कि जैसे–जैसे आप HDI के पैमाने पर ऊपर जाते हैं, यह और अधिक कठिन हो जाता है क्योंकि जीवन प्रत्याशा और स्कूली शिक्षा ऊपरी सीमा के स्तर पर पहुंच जाती है और बेहतर HDI अंक हासिल करने के लिए आमदनी वृद्धि में भी अच्छी वृद्धि लाजिमी होगी।

भारत का मानव विकास सूचकांक वर्ष 2010–21 से केवल 0.88 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ा। इसलिए, बहुत उच्च मानव विकास श्रेणी की सीमा तक पहुंचने के लिए हमें अगले 25 वर्षों के लिए इस दर को बनाए रखने की आवश्यकता होगी हालांकि ऐसा करना इतना आसान नहीं है।

भारत का HDI स्कोर 2018 में 0.647 से गिरकर 2021 में 0.633 हो गया। महामारी के कारण आमदनी को नुकसान पहुंचा लेकिन स्कूली शिक्षा और जीवन प्रत्याशा भी प्रभावित हुई क्योंकि हजारों (कुछ का अनुमान है कि लाखों) की मौत हो गई।

तुलनात्मक रूप से, महामारी के बावजूद बांग्लादेश और थाईलैंड के HDI स्कोर में वृद्धि हुई। भारत को इसलिए भी अधिक नुकसान हुआ कि विकास के अपने स्तर पर, इसके हिस्से में 77 प्रतिशत अस्थायी रोजगार (कोई निश्चित अनुबंध नहीं) का असंतुलित अनुपात में एक बड़ा हिस्सा है।

बांग्लादेश में यह 55 प्रतिशत है जहां मोटे तौर पर भारत की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ऐसे में यह वित्तीय संकट या महामारी के झटकों के लिए अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। वर्ष 2022 में 23.2 प्रतिशत पर युवा बेरोजगारी भी बहुत अधिक है। महिला श्रम बल की भागीदारी बहुत कम है और यह लगातार घट रही है। भारत को अपनी कामकाजी आबादी का उपयोग अब तक की तुलना में बेहतर तरीके से करना चाहिए। बढ़ती असमानता ने भी नुकसान पहुंचाया है।

UNDP का अनुमान है कि असमानता के कारण भारत के HDI स्कोर में 24 प्रतिशत की गिरावट है। असमानता को आधा करने से भारत का HDI स्कोर 0.7 से ऊपर बढ़ जाएगा और भारत को उच्च HDI श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। 'विकसित बनने के लिए हमें न केवल अधिक 'समृद्ध भारत' आवश्यकता है, बल्कि एक और 'समावेशी भारत' बनाने की भी आवश्यकता है।

विश्व बैंक के वर्गीकरण में 80 देशों को विकसित देश का दर्जा प्राप्त है, 104 और देश, विकसित देश बनने की इच्छा रखते हैं। इन्हें 51 निम्न–मध्यम आय और 53 उच्च–मध्यम आय वाले देशों में विभाजित किया गया है। अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे कई उच्च मध्यम आय वाले देश की स्थिति भी खस्ता है और वे तथाकथित रूप से मध्यम आय के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए सफल प्रयास करने के मकसद से आवश्यक संस्थागत साधनों का निर्माण नहीं किया।

भारत, अब एक निम्न मध्यम आय वाला देश है जिसे सबसे पहले उच्च मध्यम आमदनी वाली स्थिति तक पहुंचने के प्रयास करने चाहिए जिसके लिए वर्ष 2022 की कीमतों के लिहाज से प्रति व्यक्ति 4,255 डॉलर GNI की आवश्यकता होती है। यदि भारत, प्रति व्यक्ति GNI में 7 प्रतिशत सालाना दर से वृद्धि करता है तब यह 2032 तक उच्च आमदनी वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। यह 2022 की कीमतों के आधार पर 6–7 लाख करोड़ रुपये वाली अर्थव्यवस्था होगी जो आसानी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है लेकिन अब भी यह एक विकसित अर्थव्यवस्था की स्थिति से बहुत दूर है।

इसी तरह, UNDP में 0.7 और 0.8 के बीच के स्कोर के साथ 'उच्च' मानव विकास की श्रेणी है। इंडोनेशिया और वियतनाम में HDI 0.7 से ऊपर है। वहीं 0.633 के HDI स्कोर के साथ भारत लगभग 2032 तक उस श्रेणी में पहुंच सकता है। अगर हमने महामारी के दौरान अपने HDI में गिरावट नहीं देखी होती तब हम पहले ही उच्च मानव विकास श्रेणी में पहुंच सकते थे और ऐसा संभवतः 2030 तक हो सकता था।

अगर हम इस मध्यवर्ती चरण तक पहुंचने पर विचार करें तब मजबूत संस्थानों, बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी के साथ शीर्ष की तरफ बढ़ना एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने की बेहतर तैयारी के माफिक है। अगर हम बेस कैंप तक पहुंचते हैं लेकिन हमारे पास आखिरी कोशिश के लिए संसाधन नहीं होंगे तब हम फिर से मध्यम आय के जाल में फंस सकते हैं। एक बार मजबूत मानव पूंजी और संस्थानों के साथ भारत 100 वें स्थान पर 'विकसित भारत' की योजना बना सकता है।

लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उचित योजनाओं की रूपरेखा और सावधानीपूर्वक चयनित मध्यवर्ती लक्ष्यों के बिना बड़े लक्ष्य तय करना महज एक इच्छा साबित होगी।

(लेखक इक्रियर और जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के अतिथि प्राध्यापक हैं)

विकसित भारत सबका साथ, सबका विकास...

जगत प्रकाश नड्डा

सेवा और श्रम योगदान को विशेष रूप से मोदी सरकार द्वारा उचित सम्मान दिया गया है। संबोधन का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्र की युवा शक्ति के नाम रहा। ये देश के युवा ही हैं जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में मदद की है। ये देश के युवा ही हैं जिन्होंने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश को सिरमौर बना दिया है।

जगत प्रकाश नड्डा : देश स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वाले दौर से निकलकर अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कालजयी नेतृत्व में देश 2047 तक 'विकसित भारत' का संकल्प सिद्ध करने का लक्ष्य लेकर कर्तव्य पथ पर बढ़ चला है। गुलामी की मानसिकता को दरकिनार करते हुए आजादी की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम भी यही रही कि 'राष्ट्र पहले, हमेशा पहले।' इसकी संपूर्ण झलक हमें एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले की प्राचीर से दिए गए संबोधन में मिली। प्रधानमंत्री का संबोधन 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने का रोडमैप था। देश को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के नासूरों से मुक्त करने का एलान और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूल मंत्र को साकार करने वाला संकल्प सूत्र था। यह संबोधन प्रेरणादायी होने के साथ ही देश के विश्वास एवं सामर्थ्य को प्रतिबिंबित करने वाला था।

स्वतंत्रता दिवस पर सीमावर्ती गांवों के ग्राम पंचायत प्रधानों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को सिद्ध करता है कि वह भारत के अंतिम गांव नहीं, बल्कि प्रथम गांव हैं। कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि एवं कौशल विकास योजना के प्रतिभागी, किसान उत्पादक संगठनों के सदस्य, नई संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना के श्रम योगी, अमृत सरोवर के लिए काम करने वाले श्रम योगी, खादी श्रमिक, सीमा सड़क निर्माण में काम करने वाले श्रमिक, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, नर्स और मछुआरे भी आमंत्रित थे। एक तरह से ये संपूर्ण भारत के नवनिर्माण में काम करने वाले हरेक श्रम योगी का सम्मान था जिन्हें पिछली सरकार पूछती तक नहीं थी। सेवा और श्रम योगदान को विशेष रूप से मोदी सरकार द्वारा उचित सम्मान दिया गया है। संबोधन का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्र की युवा शक्ति के नाम रहा। ये देश के युवा ही हैं जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में मदद की है। ये देश के युवा ही हैं जिन्होंने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश को सिरमौर बना दिया है। टीयर–2 और 3 शहरों में युवा विकास के केंद्र बन गए हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि 'सुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम'– तो यह दुनिया के सामने भारत के युवाओं के सामर्थ्य का एलान था। यह इस देश की क्षमता और सामर्थ्य को दर्शाता है। साथ ही, देश को आगे ले जाने के मोदी जी के संकल्प को भी प्रदर्शित करता है। यह एक कटु सत्य है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण गरीब, पिछड़े, आदिवासियों और दलितों का हक छीनते हैं। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हमें इन्हें जड़ से मिटाना ही होगा। हजार साल की गुलामी के बाद देश मोदी जी के नेतृत्व में संवर रहा है। आज हम जो भी कदम उठाएंगे, वे हजारों साल तक देश की दिशा निर्धारित करेंगे। आज देश की मातृशक्ति सफलता के नए आयाम गढ़ रही है। देश से आतंकवाद का सफाया हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कमी आई है और वहां विकास की कहानी शुरू हुई है। विकास को गांव–गांव, घर–घर तक पहुंचाने के कारण आए सकारात्मक बदलावों और रक्षा क्षेत्र में सुधारों के कारण सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री जी के लिए सारा देश ही उनका परिवार है। इसकी झलक भी हमें उनके संबोधन में दिखी जब उन्होंने बार–बार देशवासियों को परिवार–जन कहकर संबोधित किया। यही सेवा भाव, समर्पण भाव और परिवार भाव हमें औरों से अलग करता है। यह बात दीगर है कि इस देश में ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जिसके नेता बार–बार जनता–जनार्दन का अपमान करने से भी नहीं चूकते। वे देश की जनता के लिए 'राक्षस' जैसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म अब देश की कार्यसंस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। इनके चलते नीतिगत स्थिरता, बेहतर समन्वय और ईज आफ डूइंग बिजनेस की स्थिति सुधरी है। इससे भारत एक आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने 'फ्रेजाइल फाइव' से 'टाप फाइव' की यात्रा की है और अगले पांच वर्षों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होंगे। भ्रष्टाचार के प्रति मोदी सरकार की 'जीरो टालरेंस' नीति के कारण आज सरकार की हर योजना का लाभ सभी लाभार्थियों तक बिना किसी बिचौलिए के पहुंच रहा है जिससे लाभार्थियों का सशक्तीकरण हो रहा है। डीबीटी के तहत अब तक लगभग 27 लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों के खातों में भेजे गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जन–धन, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ और पीएम आवास योजना जैसी योजनाएं जन–जन के जीवन में कल्याण लाने का माध्यम बनी हैं। यह बदलते भारत और आगे बढ़ते भारत की सुनहरी तस्वीर है।

विकसित भारत बनाने की चुनौतियां...

श्री ललित गर्ग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नया भारत निर्मित हो रहा है। मोदी के शासनकाल में यह संकेत बार–बार मिलता रहा है कि हम विकसित हो रहे हैं, हम दुनिया का नेतृत्व करने की पात्रता प्राप्त कर रहे हैं, हम आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, दुनिया के बड़े राष्ट्र हमसे व्यापार करने को उत्सुक हैं, महानगरों की बढ़ती रौनक, गांवों का विकास, स्मार्ट सिटी, कस्बों, बाजारों का विस्तार अबाध गति से हो रहा है। भारत नई टेक्नोलॉजी का एक बड़ा उपभोक्ता एवं बाजार बनकर उभरा है, ये घटनाएं एवं संकेत शुभ हैं। आज भारतीय समाज आधुनिकता के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इन रोशनियों के बीच व्याप्त घनघोर अंधेरों पर नियंत्रण करके ही भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बना सकेंगे।

हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम साहब हमेशा कहते थे, 'हेव ए बिग ड्रीम' अर्थात बड़े सपने लो। यदि आपके सपने बड़े होंगे तभी तो आप उन्हें साकार करने हेतु अधिक परिश्रम करेंगे। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश के समक्ष एक बड़ा स्वप्न रखा है कि भारत 2020 में एक पूरी तरह विकसित देश होगा, हम किसी से कम नहीं रहेंगे, सभी प्रकार से सक्षम होंगे। मोदी सरकार उसी संकल्प को पूरा करती हुई दिखाई दे रही है। बावजूद इस सकारात्मक स्थितियों के भारतीय समाज अंतर्विरोधों से भरा समाज भी है। हमारे यहां ईमानदारी एवं पारदर्शी शासन का नारा जितना बुलन्द है, कहीं न कहीं हम भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में गिने जाते हैं। आज भी हमारे यहां गरीबी बढ़ रही है, चिकित्सा, शिक्षा एवं बुनियादी जरूरतों के मामले में हमारे यहां के हालात बेहद पिछड़े एवं चिंतनीय हैं।

हालांकि हमारा राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा जनतांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन आज भी हम एक सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं बन पाए हैं। कुछ तो कारण हैं कि उम्मीद की किरणों के बीच अंधेरे भी अनेक हैं। सबसे बड़ा अंधेरा तो देश के युवा सपनों पर बेरोजगारी एवं व्यापार का छाया हुआ है। बेरोजगारी की बढ़ती स्थितियों ने निराशा का कुहासा ही व्याप्त किया गया है। हमारी उपलब्धियां कम नहीं है। हम एक महान राष्ट्र हैं। हमारी सफलताएं आश्चर्यजनक हैं, पर हम उन्हें महत्व ही नहीं देते, आखिर क्यों? इतने निराशावादी एवं नकारात्मक क्यों हैं? हमें अपनी शक्ति, क्षमता, अच्छाई स्वीकारने में क्यों परेशानी होती है? हम गेहूं और चावल उत्पादन में विश्व में अव्वल हैं। दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम हैं, बहुत से क्षेत्र हैं, जिनमें हमने उन्नति की है, पर इनका जिक्र न करके हत्या, चोरी, डकैती, अपराध, घोटालों, राजनीतिक प्रदूषण इत्यादि को ही प्राथमिकता क्यों दी जाती है।

हम असफलताओं की ही चर्चा करते हैं, उन्हीं को हाईलाइट करते हैं, आखिर क्यों? उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, हम विदेशी वस्तुओं के प्रति क्यों मोहग्रस्त हैं? अपनी इंपोर्टेड गाड़ी, घड़ी, टीवी, कैमरा, छाता, टाई, पेन, पेंसिल जो भी विदेशी है उसके प्रति गर्व अनुभव करते हैं। हमें सब कुछ यथासंभव विदेशी पसंद है। हम यह क्यों नहीं समझते कि स्वाभिमान आत्मनिर्भरता की दिशा में अपेक्षित ही नहीं, अपरिहार्य है। एक विकासशील भारत के रूप में और हमने वस्तुतः तकनीकी क्षेत्रों में प्रशंसनीय प्रगति की है। कम्प्यूटर के क्षेत्र में हम अग्रणी हैं, हमारी सेनाएं हमारी अपनी ही मिसाइलों, अपने ही आयुधों–उपकरणों से संपन्न हैं, पर हम सच्चे अर्थों में विकसित नहीं हैं।

विश्वविद्यालय, कॉलेज आदि नई आधुनिकता का माध्यम बन रहे हैं, किंतु अगर हम सही अर्थों में देखें तो भारतीय समाज में आज भी अनेक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, वंशवाद आदि का दंश हमारे विकास या आधुनिकता में अंतर्विरोध पैदा करते रहते हैं। खाप पंचायतें आज भी धड़ल्ले से गांवों में कानून का मखौल बनाती हैं। जनतंत्र एवं जनतांत्रिक राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं संप्रदायवाद की भूमिका सीधे तौर पर देखी जा सकता है। भारत एक जनतांत्रिक समाज तो है, लेकिन उसमें सामंती मूल्य का होना एक तरह का अंतर्विरोध

सृजित कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह समाज आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, किंतु अन्तर्विरोधों एवं पूर्वाग्रहों के साथ।

भारत अहिंसक देश है। अहिंसा के मूल्यों पर विश्वास करता है, किंतु अगर गहराई से देखें तो यहां के सामाजिक स्तरों में हिंसा की अनेक परतें दिखाई पड़ेंगी। हमारे शिक्षा के मन्दिर आज हिंसा के अखाड़े बने हुए हैं, छोटे–छोटे बच्चे हिंसा की घटनाओं को अंजाम देते हैं, कोई प्रिन्सिपल को गोली मार देता है तो कोई अपने ही सहपाठी की दर्दनाक एवं बर्बर हिंसा कर देता है। हमारे समाज की पृष्ठभूमि भी हिंसा से त्रस्त है, बुजुर्गों पर हम अत्याचार करते हैं, उन्हें अनाथालयों के हवाले कर देते हैं, हमारे समाज में कई बार बाप बेटे को पीटता है। पति पत्नी को पीटता है, आधिपत्यशाली कमजोर पर हिंसा करता है। हर शक्तिवान शक्तिहीन को हिंसा के माध्यम से ही नियंत्रित करना चाहता है।

इस तरह के दुखद विरोधाभास से भारत का विकास एवं नए भारत का संकल्प कभी–कभी बेमानी लगता है। कहने को तो हम बुद्ध, महावीर के उपदेशों की दुहाई देते हैं। अपने को गांधी का देश कहते हैं और अहिंसा की महत्ता को रेखांकित करते हैं, किंतु अनेक बार अपनी असहमति एवं विरोध हिंसा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। कभी गौरक्षा के नाम पर तो कभी राष्ट्रगान को लेकर, कभी हम बिना सोचे–समझे पद्मावत जैसी फिल्मों के नाम पर हिंसा पर उतारु हो जाते हैं, इस क्रम में कभी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाती है, कभी अपने से भिन्न मत रखने वाले को और कभी–कभी निर्दोष भारतीयों को भी क्षति पहुंचा देते हैं। किस तरह से हम अपने को विकसित कह सकते हैं?

भारतीय समाज में हिंसा बढ़ी है या यूं कहें हिंसा का राजनीतिकरण हुआ है। स्थानीय निकाय चुनावों से लेकर संसद के लिए होने वाले चुनाव में भी हिंसा के अनेक रूप पूरी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में दिखाई देते हैं। किसी को वोट देने पर हिंसा, किसी को वोट न देने पर हिंसा, हिंसा के बल पर राजनीतिक ताकत दिखाने की होड़। एक तरह से अनेक रूपों में हिंसा हमारी चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र का अभिन्न अंग बन गई है। आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह, ऐसे लोग गिनती के मिलेंगे जो इन तीनों स्थितियों से बाहर निकलकर जी रहे हैं। पर जब हम आज राष्ट्र की राजनीति संचालन में लगे अगुओं को देखते हैं तो किसी को इनसे मुक्त नहीं पाते।

सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच संसद में आज संवाद नहीं, विवाद अधिक दिखाई देते हैं। उस पटल पर सरकार के किए वायदों के अधूरे रहने पर भी प्रश्न करें, भ्रष्टाचार समाप्त करने और शासन में पारदर्शिता लाने से जुड़े सवाल हो, कश्मीर समस्या की चर्चा हो और पाकिस्तान को सबक सिखाने के मुद्दे हों, देशभर में सामाजिक समरसता बढ़ाने की बात हो, यह सब सार्थक चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन इन चर्चाओं की जगह देश में हो रहे बुनियादी कामों की टांग खिंचाई कैसे लोकतंत्र को सुदृढ़ कर पाएंगी। जब नया भारत निर्मित करने की बात हो रही है।

जब सबका साथ–सबका विकास की बात हो रही है, तो उनमें खोट तलाशने की मानसिकता कैसे जायज हो सकती है? शिक्षा की कमी एवं निम्नस्तरीय जीवनयापन गरीबी को बनाए हुए है। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं रोगों की रोकथाम हेतु व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। कमजोर एवं बीमार लोगों की शक्ति की कमी उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। सूचना संचार तकनीक के सृजनात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण/सार्थक उपयोग द्वारा भारत को एक नई शक्ल देने की बात कर रहे हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था डिजिटलाइज एवं ऑनलाइन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे यहां इंटरनेट की क्षमता एवं तकनीक संतोषजनक नहीं है।

आज जब पानी के लिए एक राज्य दूसरे के विरुद्ध मुकदमा करता है, एक भाषा–भाषी को दूसरे की भाषा नहीं सुहाती, संसद जो धैर्यपूर्वक सुनने–बोलने, सोचने–समझने की जगह है वहीं अनुशासन की जगह हंगामा होता है, राष्ट्र के तथाकथित सेवक कुर्सी के पुजारी और देश के भक्षक बन रहे हैं, राजनीति और नैतिकता का संबंध विच्छेद होता जा रहा है, सांस्कृतिक एवं जीवन मूल्यों से परे हटकर भोगवाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्र के पूर्ण विकसित होने के स्वप्न का साकार होना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। राष्ट्र को सच्चे अर्थों में जागना होगा, फिर कितना ही बड़ा स्वप्न क्यों न हो, अवश्य पूरा होगा।

वस्तुतः मोदी साहब के सपनों का विकसित भारत तभी संभव है, जब नैतिक, चारित्रिक एवं अनुशासन की दृष्टि से हम उन्नत होंगे तथा राजनीति अपराध का व्यापार न बनकर देशसेवा का आधार बनेगी। यदि हम संकल्प एवं समर्पण भाव, आत्मविश्वास एवं नैतिकता के साथ आगे बढ़ेंगे तथा देश को अपने निजी स्वार्थों से ऊपर मानकर चलेंगे तो निश्चय ही सभी क्षेत्रों में हम पूर्ण विकसित होकर विश्व में अग्रणी हो सकेंगे अन्यथा हमारी प्रगति चलनी में भरा हुआ पानी होगा, प्रतिभासित किंतु असत्य। वह राष्ट्रीय जीवन के शुभ को आहत करने वाला है।

नए भारत के शिल्पी अटल जी

राष्ट्रहित एवं राष्ट्र प्रथम के मन्त्र को अपने जीवन का ध्येय बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी के लि ए देश से अलग कुछ भी महत्वहीन था। काल के कपाल पर लिखने का बल भी अटल जी के पास था और कौशल भी अटल जी के ही पास था।

भारत की इस वीर,पूण्य व प्रतापी भूमि पर 25 दिसंबर के दिन का ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन एक ओर जहां भारत को विश्व के शैक्षिक क्षितिज पर प्रतिष्ठित करने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी वहीं दूसरी ओर भारत के राजनीतिक कौशलता एवं लोकतंत्र की पवित्रता से विश्व को परिचित कराने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। भारत के इन दोनों महान सपूतों को अपनी आदरांजलि अर्पित करते हुए हम यह कह सकते हैं कि इन विद्वान् द्वय ने भारत की वैचारिक समृद्धि, सास्कृतिक विविधता को विश्व के कोने–कोने तक पहुंचाने का कार्य किया है। हम यदि अटल जी के जीवन, उनके विचार, उनके आदर्शों एवं मूल्यों से कुछ भी सीखने का प्रयास करेंगे तो वे हमें सदैव अटल रहना ही सिखाती हैं। स्वतंत्रता के पश्चात इक्कीसवीं सदी के सुरक्षित, सक्षम एवं सुदृढ़ भारत की नींव रखने वाले यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे।

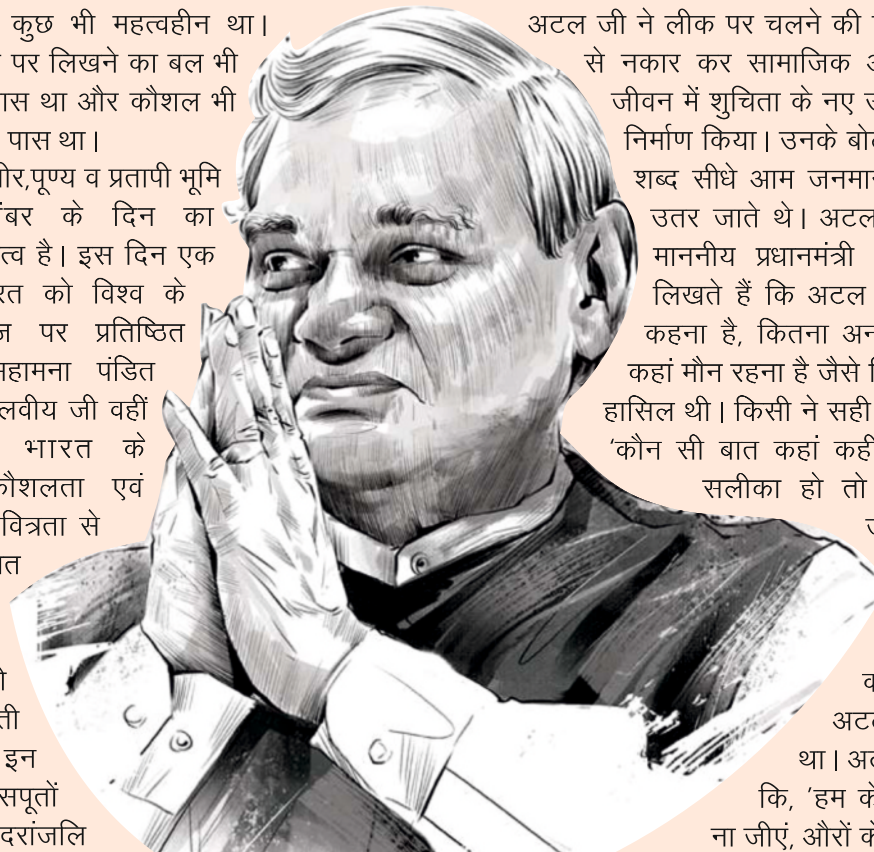

जन्मदिन विशेष

राष्ट्रहित एवं राष्ट्र प्रथम के मन्त्र को अपने जीवन का ध्येय बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए देश से अलग कुछ भी महत्वहीन था। काल के कपाल पर लिखने का बल भी अटल जी के पास था और कौशल भी अटल जी के ही पास था। यह सत्य भी है एवं तथ्य भी है कि अटल जी ने लीक पर चलने की परम्परा को सिरे से नकार कर सामाजिक और राजनीतिक जीवन में शुचिता के नए उच्च मापदंड का निर्माण किया। उनके बोले गए एक–एक शब्द सीधे आम जनमानस के ह्रदय में उतर जाते थे। अटल जी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि अटल जी को कितना कहना है, कितना अनकहा रखना है, कहां मौन रहना है जैसे विषयों में महारथ हासिल थी। किसी ने सही ही लिखा है कि 'कौन सी बात कहां कही जाती है! यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है!' इस लाइन को सही मायनों में चरितार्थ करने का कार्य अटल जी ने किया था। अटल जी कहते थे कि, 'हम केवल अपने लिए ना जीएं, औरों के लिए भी जीएं... हम राष्ट्र के लिए अधिकाधिक त्याग करें। अगर भारत की दशा दयनीय है तो दुनिया में हमारा सम्मान नहीं हो सकता। किंतु यदि हम सभी दृष्टियों से सुसंपन्न हैं तो दुनिया हमारा सम्मान करेगी।'

राष्ट्र के प्रति सार्थक चिंतन मनन करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के विजय एवं विकास के स्वर थे। वे एक ऐसे मनीषी थे जिन्हें भारत की जनता ने पांच दशक तक अपने हित की राजनीति करने के लिए चुना था। देश के समग्र विकास के प्रति सतत प्रयासरत रहने वाले अटल जी की दृष्टि में भारत का सच्चे अर्थों में विकास तभी संभव था जब यहाँ के प्रत्येक नागरिक भूख, भय, निरक्षरता और अभाव के भाव से मुक्त होकर

अपना जीवन जिए।

डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों का अनुसरण करने वाले अटल जी ने अनेकों बार पार्टी लाइन से उपर उठकर राष्ट्र के जरूरी विषयों पर हस्तक्षेप किया और देखते ही देखते अटलजी की छवि एक स्टेट्समैन की हो गई, उन्होंने अपने सिद्धांतों व राजनीतिक आचार–व्यवहार से सबको प्रभावित किया। अटल जी एक ऐसे नेता माने जाते थे जो किसी भी विवाद को संवाद की ओर लेकर जाते थे। उनमें संभावनाओं की तलाश करते थे और यही कारण है कि अटल जी आज भी सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन–मस्तिष्क में ज्ञानस्वरूप बनकर स्थापित हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जहां स्वतंत्रता के पश्चात एक राजनीतिक पार्टी का एकछत्र राज था, उस दल के तिलिस्म को ध्वस्त कर भारतीय नागरिकों को राजनैतिक विकल्प प्रदान किया, जब सम्पूर्ण देश में कांग्रेस का वर्चस्व था तब जनसंघ जैसे नए दल और उस दल का झंडा थामे युवा अटल, दोनों के लिए रास्ते आसान नहीं थे। 1957 में जब अटल जी लोकसभा के लिए चुने गए, तब संसद में जनसंघ संख्याबल के आधार पर कांग्रेस के समक्ष चुनौती नहीं दे पा रही थी लेकिन अटल जी ने जनसंघ को वैचारिक रूप से इतना मजबूत बना दिया कि संख्या बल मात्र एक शब्द बन कर रह गया। उनके भाषण, उनके विचार कांग्रेसी सत्ता की पेशानी पर बल ला देते थे।

यहां यह जिक्र करना अति आवश्यक है कि अटल जी का एक लम्बा राजनीतिक समय विपक्षी नेता के रूप में व्यतीत हुआ है लेकिन हमेशा वे सरकार की नीतियों उसकी कार्यप्रणालियों को लेकर विरोध ही करते रहे ऐसा नहीं था। पाकिस्तान से युद्ध के दौरान अटल जी ने अपना विरोध किनारे रख दिया। उन्होंने सरकार को अपना समर्थन दिया। राजनीति की जगह उन्होंने राष्ट्रनीति को महत्त्व दिया।ऐसे सैकड़ो उदाहरण हमें अटल जी से जुड़े मिल जायेंगे। क्या आज हम जब देशहित से जुड़े विषयों पर प्रमुख विपक्षी दलों से यह उम्मीद कर सकते हैं कि वे सरकार के समर्थन में एक भी शब्द बोल सकेंगे? दुर्भाग्य से यह उम्मीद बेईमानी होगी।

अटल जी को भारतीय राजनीति का अजातशत्रु कहा जाता रहा है। इसके पीछे यूँ तो अनेकों उदाहरण हैं स्वयं प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु अटलजी जी में देश का राजनीतिक भविष्य देखते थे, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, श्री चन्द्रशेखर, लोहिया जी हर कोई उनके विचारों गंभीरता से सुनता था वह संसद में बोलने के लिए खड़े होते थे तो सत्ता पक्ष हो अथवा विपक्ष सभी उनके एक–एक शब्द को सुनने व समझने के लिए आतुर रहते थे।

प्रधानमंत्री रहते हुए देश को परमाणु सम्पन्न बनाने की दृढ़ इच्छाशक्ति हो अथवा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, शिक्षा और एम्स को विस्तार देना हो अथवा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दृढ़ करना अटलजी जी नए भारत के शिल्पी थे, सुशासन के प्रतीक थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अटलजी व महामना मालवीय जी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में सार्थक कदम बढ़ा रहा है।आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में हमारा कर्तव्य है कि देश के लिए खुद को खपाने वाले हमारे प्रेरणास्रोत श्री अटलजी जी के विचारों को जन–जन से जोड़े तथा अभाव से मुक्त भारत के संकल्प को सिद्धि की तरफ ले जाएं। हम सभी मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए अपना सहयोग दें।

(लेखक केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री हैं)

मोदी की तकनीकी दृष्टि और योजनाएँः विकसित भारत को लगा पंख

जब हम "नये भारत" की बात करते हैं; जब हम विकसित भारत की बात करते हैं; जब हम मॉडीफ़ाइड इंडिया की बात करते हैं तो एक बात अपने आप दिमाग में तैरने लगती है वह है तकनीकी नवाचार अथवा तकनीकी हस्तक्षेप।

भारत जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक तिरंगा लहराने में कामयाब हुआ तो फिर यह विमर्श दुनिया में शुरू हो गई कि तकनीकी के मामले में भारत दुनिया का सिरमौर बन रहा है, बादशाह बन गया है।

बात चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, मशीन लर्निंग की हो, क्वांटम फिजिक्स की हो, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की हो, परिवहन में हो रही ईंधन क्रांति की हो अथवा संचार क्रांति के क्षेत्र में 5ळ के बढ़ते कदम की हो, टेली मेडिसिन की बात हो, नैनो यूरिया की बात हो, खेती में ड्रोन के इस्तेमाल की बात हो, बैंक में हो रही क्रांति की बात हो, बिजली के क्षेत्र में हो रहे तकनीकी परिवर्तन की चर्चा हो अथवा पढ़ाई के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की चर्चा हो, एक बात तो सबके मन में है कि भारत में सुशासन की गाड़ी तकनीकी के सहारे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है।अब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां तकनीकी विकास के बिना विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती? आम आदमी की जिंदगी में सुख नहीं लाया जा सकता है? खेती में बदलाव नहीं हो सकते? उद्योगों में क्रांति नहीं हो सकती और सेवा क्षेत्र में हम उड़ान नहीं भर सकते? यदि भारत को दुनिया की सशक्त अर्थव्यवस्था में शीर्ष पर प्रतिस्थापित होना है तो उसे तकनीकी के क्षेत्र में पहले ही शीर्ष पर स्थापित होना पड़ेगा और उस दिशा में यह देश तेजी से आगे बढ़ चला है।

आइए हम देखें कि 2014 के बाद से किस तरह से तकनीकी इस देश के स्वरूप को बदल रही है? कैसे लोगों की जिंदगी में सहजता आ रही है? परिवर्तन आ रहा है? उन्नति हो रही है?

विकसित भारत के लिए मोदी सरकार की तकनीकी योजनाएँ

- **डिजिटल इंडियाः** राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड, ई–गवर्नेंस, डिजिटल साक्षरता, स्टार्टअप।
- **आधारः** प्रत्येक नागरिक के लिए विशिष्ट आईडी प्रणाली, सेवाओं और लाभों तक पहुंच की सुविधा।
- **यू.पी.आईः** एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस – सभी प्लेटफार्मों पर मोबाइल–आधारित कैशलेस लेनदेन।
- **उमंगः** सरकारी सेवाओं के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप – 600 से अधिक केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं के लिए एकल मंच।
- **ई–गवर्नेंस पहलः** विभिन्न सरकारी सेवाओं जैसे पासपोर्ट आवेदन, भूमि रिकॉर्ड, व्यवसाय लाइसेंस आदि के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म।
- **डिजिटल सेवा पोर्टलः** सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच।
- **भारतनेटः** गांवों को हाई–स्पीड ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड से जोड़ना।
- **डिजिटल भुगतान मिशनः** यूपीआई, ई–वॉलेट आदि के माध्यम से कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देना।
- **साइबर सुरक्षा पहलः** मजबूत साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे और जागरूकता कार्यक्रमों की स्थापना।
- **मेक इन इंडियाः** इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा आदि क्षेत्रों में स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करना।
- **आत्मनिर्भर भारत अभियानः** भारत को रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आईटी आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएंः** सेमीकंडक्टर, उन्नत सेल रसायन बैटरी, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना।
- **स्टार्टअप इंडिया पहलः** इनक्यूबेटर, एक्सेलेरेटर, फंडिंग स्कीम, मेंटरशिप प्रोग्राम आदि के माध्यम से स्टार्टअप का पोषण करना।
- **स्टार्टअप्स के लिए इनोवेशन फंडः** होनहार स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **ई–संजीवनीः** ग्रामीण मरीजों को शहरी क्षेत्रों के डॉक्टरों से जोड़ने वाला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म।
- **स्वयंः** स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा तक शैक्षिक पाठ्यक्रमों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने वाला ऑनलाइन शिक्षण मंच।
- **डिजिटल इंडिया ईविद्या कार्यक्रमः** स्कूली शिक्षा सामग्री को डिजिटल बनाना और ई–लर्निंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- **आरोग्य सेतु ऐपः** महामारी के दौरान संपर्कों का पता लगाने और COVID–19 सूचना प्रसार के लिए विकसित किया गया।
- **आरोग्य सेतु मित्र योजनाः** सामुदायिक स्वयंसेवकों को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करें।
- **डिजीगॉव इनोवेशन चैलेंजः** सामाजिक कल्याण के मुद्दों के लिए प्रौद्योगिकी समाधान को प्रोत्साहित करें।
- **राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस पुरस्कारः** ई–गवर्नेंस परियोजनाओं में उत्कृष्टता को मान्यता देना।

- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणः** बिचौलियों को दरकिनार करते हुए, डीबीटीएल पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए डिजिटल रूप से सीधे नागरिकों की जेब में सब्सिडी डालता है। अब तक ३३.४३ लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खाते में डाला जा चुका है जिससे लाखों–करोड़ों रुपए बिचौलियों के जेब में जाने से बच गये।
- **डिजिटल कूटनीतिः** अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव और सहयोग के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
- **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मिशनः** चंद्रयान , गगनयान (अंतरिक्ष में पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री), मंगल ऑर्बिटर मिशन, आदि।
- **अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोगः** अंतरिक्ष अन्वेषण और उन्नत प्रौद्योगिकियों पर अन्य देशों के साथ सहयोग करना।
- **कौशल भारत मिशनः** डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए कार्यबल को उन्नत बनाना।
- **डिजिटल साक्षरता मिशनः** नागरिकों को बुनियादी डिजिटल कौशल और इंटरनेट उपयोग पर प्रशिक्षित करना।
- **एआई मिशनः** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- **राष्ट्रीय खुला सरकारी मंचः** सरकारी डेटा और डेटासेट तक सार्वजनिक पहुंच।
- **ओपन सोर्स मिशनः** सरकार के भीतर ओपन–सोर्स सॉफ़्टवेयर का विकास और उपयोग।

2014 के पहले, भारत में डिजिटल विभाजन एक गहरी खाई थी, जो शहरी समृद्धि और ग्रामीण अलगाव के बीच एक दीवार का काम कर रही थी। इंटरनेट का उपयोग एक विलासिता थी, डिजिटल साक्षरता एक सपना था, और ऑनलाइन लेनदेन लाखों लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ था। इस असमानता को पहचानते हुए, मोदी सरकार ने केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई से इस अंतर को पाटने का मिशन शुरू किया।

भारतनेटः कनेक्टिविटी का जाल बुन रहा है –

फाइबर ऑप्टिक केबलों से बुनी गई एक विशाल जाल की कल्पना करें, जो 66% ग्राम पंचायतों में निवासरत भारतीयों तक फैली हुई है। भारतनेट, ग्रामीण समुदायों को उच्च–गति वाले ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना। भारतनेट का असर चौंकाने वाला है। किसान अब सीधे ऑनलाइन खरीदारों से जुड़कर अपनी फसलों के लिए अधिक कीमत प्राप्त कर रहे हैं। छात्र स्वयं जैसे ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफार्मों के माध्यम से भौगोलिक सीमाओं को पार करके अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। ई–संजीवनी जैसी पहलों के माध्यम से वंचित क्षेत्रों में मरीजों को दूरस्थ परामर्श प्राप्त हो रहा है।

भारतनेट का मतलब है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब शहरी क्षेत्रों के लोगों के समान अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। यह भारत को एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद कर रहा है।

आधार और JAM से सशक्तीकरण

आधारः पहचान प्रबंधन में क्रांति

आधार, 1.3 अरब से अधिक भारतीयों के पास मौजूद एक अद्वितीय बायोमेट्रिक पहचानपत्र है, देश की डिजिटल क्रांति की रीढ़ है। यह पहचान प्रबंधन में क्रांति ला चुका है, धोखाधड़ी को समाप्त कर दिया है और सरकारी सेवाओं की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित की है।

आधार ने पहचान प्रमाणीकरण को आसान और अधिक सुरक्षित बना दिया है। यह सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक है, जैसे कि पेंशन, छात्रवृत्ति और सब्सिडी। आधार के माध्यम से, सरकार अब लाभार्थियों की पहचान को सत्यापित कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि योजनाएं सही लोगों तक पहुंच रही हैं।

JAM: वित्तीय समावेशन में गेम–चेंजर

जन धन योजना (Jan Dhan Yojana), आधार और मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी वित्तीय समावेशन में एक गेम–चेंजर बन गई है। इसने 50 करोड़ से अधिक लोगों को बैंक खाते खोलने में मदद की है, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

JAM ट्रिनिटी ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में भी मदद की है। यूपीआई (Unified Payments Interface), दुनिया की सबसे बड़ी वास्तविक समय भुगतान प्रणाली, के माध्यम से 120 बिलियन से अधिक लेनदेन संसाधित किए गए हैं। इससे कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा मिला है और उन लाखों लोगों को सशक्त बनाया है जिनके पास पहले बैंकिंग सुविधा नहीं थी।

आधार, JAM और भारतनेट जैसी पहलों का प्रभाव महज़ आँकड़ों से परे है। वे भारत भर के लोगों के जीवन को वास्तव में बदल रहे हैं।

पूर्ण डिजिटल समावेश की यात्रा चुनौतीपूर्ण ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं। डिजिटल साक्षरता की खाई को पाटना, हर कोने तक वहनीय इंटरनेट पहुँचाना और डेटा गोपनीयता की

चिंताओं का समाधान करना महत्वपूर्ण कदम हैं। लेकिन गति निर्विवाद है, और डिजिटल परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अटूट बनी हुई है।

बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और नवाचार में निरंतर निवेश के साथ, भारत डिजिटल युग में वैश्विक नेता बनने की ओर अग्रसर है। जैसे–जैसे डिजिटल धागे समाज के ताने–बाने में गहराई से गुंथते जाते हैं, हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जहां हर किसी के लिए मेज पर एक स्थान होगा।

सिलिकॉन वैली को अक्सर नवाचार का केंद्र माना जाता है, लेकिन भारत तेजी से एक वैश्विक नवप्रवर्तक बन रहा है। भारत की उद्यमशीलता की भावना और तकनीकी कौशल से प्रेरित होकर, भारतीय स्टार्टअप अरबों डॉलर के सपनों को साकार कर रहे हैं।

स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडियाः विचारों को विकसित करना, सपनों को प्रज्वलित करना

भारतीय स्टार्टअप परिदृश्य में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत में 110 से अधिक यूनिकॉर्न (1 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य वाले स्टार्टअप) थे। इनमें से कई स्टार्टअप वित्तीय प्रौद्योगिकी, ई–कॉमर्स, और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में हैं।

प्रधानमंत्री मोदी सरकार का स्टैंडअप इंडिया योजना युवाओं और महिलाओं के उद्यमशीलता के सपनों को पंख लगाने का एक प्रेरक कदम है। यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित करती है। 10 लाख रुपये तक के ऋण की गारंटी के साथ, स्टैंडअप इंडिया योजना इन समुदायों को आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करती है। इससे रोजगार सृजन बढ़ता है, महिला सशक्तिकरण को बल मिलता है और पूरे देश का आर्थिक विकास गति पकड़ता है। भारत के आत्मनिर्भर बनने की राह पर स्टैंडअप इंडिया एक महत्वपूर्ण संबल है।

भारतीय सरकार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने कई कार्यक्रमों और नीतियों की शुरुआत की है जो स्टार्टअप को समर्थन प्रदान करती हैं जैसे दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (क्क्ल्ळज्ञ्ल) ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देती है।

स्मार्ट सिटी से स्मार्ट समाधान तकः भारत की नवप्रवर्तन यात्रा

भारत में नवाचार की एक क्रांति हो रही है। यह बोर्डरूम और एक्सेलेरेटर तक ही सीमित नहीं है। स्मार्ट सिटी मिशन जैसी पहल शहरी परिदृश्य में आमूलचूल बदलाव कर रही है।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, भारत सरकार 100 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए काम कर रही है। इन शहरों में, तकनीकी नवाचार का उपयोग शहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है।

उदाहरण के लिए–

- शहरों ने ट्रैफ़िक लाइटों को वास्तविक समय की भीड़भाड़ के अनुकूल बनाने के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। इससे यातायात प्रवाह में सुधार और प्रदूषण में कमी आई है।
- शहरों ने अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को विकसित किया है जो बिन ओवरफ़्लो की भविष्यवाणी करती हैं। इससे अपशिष्ट प्रबंधन में दक्षता में सुधार हुआ है।
- शहरों ने ऊर्जा ग्रिड को विकसित किया है जो बिजली के उपयोग को अनुकूलित करते हैं। इससे ऊर्जा की बचत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है।
- भारत के स्मार्ट शहर नवाचार के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान कर रहे हैं। ये शहर अधिक टिकाऊ और कुशल भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

अटल टिंकरिंग लैब्सः जहां जिज्ञासा का मिलन नवाचार से होता है

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है जो टिंकरिंग लैब और इन्क्यूबेशन केंद्रों को संगठित करता है और युवा दिमाग में रचनात्मकता को प्रज्वलित करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। छात्र अब प्रौद्योगिकी के निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं हैं, बल्कि वे इसके वास्तुकार बनने के लिए सशक्त हैं। एआईएम एक पीढ़ी का विकास कर रहा है जो ड्रोन बनाने से लेकर पर्यावरण–अनुकूल समाधान विकसित करने तक, भारत के तकनीकी परिदृश्य को आकार देगी।

मेक इन इंडियाः निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक

भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बड़े कदम उठा रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी महत्वाकांक्षी पहलें विदेशी निर्भरता कम कर, देश में ही विनिर्माण को बढ़ावा दे रही हैं। स्मार्टफोन से लेकर दवाइयों तक, ये पहलें स्थानीय उत्पादन को 25% तक बढ़ा चुकी हैं और 2022 में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा की हैं।

कुछ प्रमुख कदमः

- निवेश आसान बनाने के लिए नियमों को सरल बनाना।
- विनिर्माण के लिए बुनियादी ढांचे में 50 लाख करोड़ का निवेश।
- स्वदेशी तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ का फंड।

भारत का डिजिटल उदय अपरिहार्य है। यह एक ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले वर्षों में, भारत न केवल तकनीकी नवाचार का एक केंद्र होगा, बल्कि यह वैश्विक परिदृश्य को भी आकार देगा।

भारत की डिजिटल कहानी सिर्फ कोड और सर्वर से ज्यादा है। यह जुनून, उद्यम और क्षमता का एक अद्भुत मिश्रण है। युवा भारतीय दिमाग रचनात्मक सीमाओं को तोड़ रहे हैं और दुनिया को बदलने वाले समाधान तैयार कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर महानगरों तक, उद्यमी नया भारत गढ़ रहे हैं,

एक ऐसा भारत जो प्रौद्योगिकी के बल पर प्रगति करता है। चाहे वह कृषि में क्रांति लाने वाले ऐप हों या शिक्षा को सुलभ बनाने वाले प्लेटफॉर्म, भारत के नवाचार दुनिया को छू रहे हैं। देश तेजी से डिजिटल होता जा रहा है, और इसकी ऊर्जा अथाह है।

मोदी सरकार के तहत भारत की तकनीकी यात्रा अभूतपूर्व रही है। साहसपूर्वक ब्रह्मांड में प्रवेश करने से लेकर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में अंतराल को पाटने तक, राष्ट्र विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ रहा है, और नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में अपनी क्षमता साबित कर रहा है।

नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ना: भारत का अंतरिक्ष अभियान

मोदी सरकार के तहत भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने लंबी छलांग लगाई है। चंद्रयान–3, जिसने महज ₹978 करोड़ की लागत से चंद्रमा की सतह को छुआ, ने भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। 14 सेंसर और उपकरणों से लैस इस मिशन ने चंद्रमा के भूविज्ञान और वातावरण को 5000 से अधिक शानदार तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से हमारे सामने ला दिया।आगामी गगनयान मिशन, जिसका लक्ष्य पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना है, अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

सुरक्षा को मजबूत करना: आत्मनिर्भर भारत का निर्माण

रक्षा में आत्मनिर्भरता के महत्व को पहचानते हुए, सरकार ने स्वदेशी हथियारों के विकास और आधुनिकीकरण में निवेश को काफी बढ़ावा दिया है। भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रमाण तेजस फाइटर जेट अब भारतीय वायु सेना का मुख्य आधार है। इसके अतिरिक्त, परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी में प्रगति ने भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया है, जो इसकी बढ़ती रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।

भारत का रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2022–23 में लगभग 16,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू लिया है।

सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा: ग्रामीण–शहरी विभाजन को पाटना

ई–संजीवनी जैसी टेलीमेडिसिन पहल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में क्रांति ला रही है। वीडियो परामर्श के माध्यम से रोगियों को दूर से डॉक्टरों से जोड़कर, ई–संजीवनी चिकित्सा विशेषज्ञता और भौगोलिक रूप से अलग–थलग समुदायों के बीच अंतर को पाट रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि दूरदराज के गांवों के लोगों को भी समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल मिल सके, जो स्वास्थ्य देखभाल समानता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जनता के लिए शिक्षा: सबको समान अवसर

SWAYAM जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म देश भर के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री प्रदान करके शिक्षा का लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं। स्कूल पाठ्यक्रम से लेकर उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों तक, SWAYAM ज्ञान का एक विशाल भंडार प्रदान करता है जो इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ है। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशाली है जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच परंपरागत रूप से सीमित रही है, जिससे भावी पीढ़ी के लिए अधिक शिक्षित और सशक्त होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

मोदी सरकार के तहत भारत की तकनीकी यात्रा एक आशाजनक भविष्य की ओर इशारा करती है। सरकार की प्रौद्योगिकी पर जोर, नवाचार को बढ़ावा देने और जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत में हुए तकनीकी बदलाव की कथा पढ़ने और समझने के बाद मन में एक बात तो आती है कि भारत बदल रहा है और बदलाव का वाहक बनी है तकनीकी। बात चाहे अंतरिक्ष की हो या हवा में चल रही ध्वनि तरंगों की या धरती पर बिछ रहे ऑप्टिकल फाइबर की हो या बिजली के दौड़ते हुए तार हों या एक्सप्रेसवे पर रफ्तार भरती गाड़ियां, परिवहन में बदलती तस्वीर हो अथवा अस्पतालों में टेलीमेडिसिन की कहानी, रोबोट सर्जन का स्थान ले रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग के सहारे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, अस्पतालों में डॉक्टर, दुकान पर सेल्समैन की जगह पर अनेक तकनीकी मॉडल दृश्यमान होकर अचंभित कर रहे हैं। एक ऐसा अचंभा जो सच है, जो सामने है, जो श्रेष्ठ भी है। इस कथा के पीछे बैठा एक इंजीनियर है, एक तकनीकी विद है और इस कहानी के पीछे भारत में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी जी हैं जो गांव के एक प्राथमिक स्कूल से शिक्षा ग्रहण कर के देश की परिस्थिति के अनुकूल नए प्रतिमान बना रहे हैं और उनकी सारी सोच के पीछे एक सपना छिपा हुआ है कि आम आदमी की जिंदगी में तकनीकी के सहारे श्रेष्ठता का बीज कैसे बोया जाए? साक्षमता का बीज कैसे बोया जाए? उसके जीवन में सुख और समृद्धि का समावेश कैसे हो? जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की श्रेष्ठ 5 अर्थ वयस्थाओं में शुमार होने लगी है ,जब 2014 के बाद से अब तक के प्रयासों से 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठकर आर्थिक आजादी के मायने समझने लगे हैं तो एक चीज पर भरोसा तो बना है कि तकनीकी न केवल विकसित भारत के सपने को साकार करने में सक्षम हो सकती है।

अन्त्योदय को साकार करता ''सुशासन''

डॉ0 सौरभ मालवीय

प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दस वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। उन्होंने 26 मई, 2014 को प्रथम बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के पश्चात घोषणा की थी कि उनकी सरकार जनहित के लिए कार्य करेगी तथा अन्तयोदय के लिए कार्य करेगी। उन्होंने अपनी घोषणा में जो शब्द कहे, उस पर वह शत–प्रतिशत खरे सिद्ध हुए। उनके अब तक के संपूर्ण कार्यकाल पर दृष्टि डालें तो यह सेवा एवं सुशासन पर ही केन्द्रित रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सुशासन राष्ट्र की प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा मंत्र, उद्देश्य व सिद्धांत नागरिकों को प्राथमिकता देने का है। मेरा सपना सरकार को लोगों के समीप लाने का है, ताकि वे प्रशासनिक प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार बन सकें। सरकारी कामकाज की प्रक्रिया को आसान कर आसानी से सुशासन सुनिश्चित किया जा सकता है। उनका कहना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां के नागरिक शासन का हिस्सा बनने के लिए अत्यधिक उत्साहित हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी होना बहुत महत्वपूर्ण घटक है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के शासन में किए गए विभिन्न पहलों और सुधारों के बारे में लिखते रहते हैं। उनके शब्दों में– "130 करोड़ भारतीयों ने फैसला किया है कि वे भारत को आत्मानिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भरता पर हमारा जोर, वैश्विक समृद्धि में योगदान करने की दृष्टि से प्रेरित है। हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है, जो प्रत्येक भारतीय का ध्यान रखती है और उसके लिए चिंतित रहती है। हम लोक–केंद्रित और मानवीय दृष्टिकोण से प्रेरित हैं। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने लोक–समर्थक शासन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं, जो गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं और वंचित समुदाय की मदद करते हैं।"

वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्तयोदय के मूल तत्वों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस समयावधि में उन्होंने विश्वभर के अनेक देशों में यात्राएं करके उनसे संबंध प्रगाढ़ बनाने का प्रयास किया है। इससे विश्व के अनेक देशों के साथ भारत के संबंध बेहतर हुए तथा उनके साथ अनेक रक्षा एवं व्यापारिक समझौते भी हुए। उन्होंने देश में लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए अनेक जनकल्याण की योजनाएं प्रारम्भ की हैं। मोदी सरकार ने विकास का नारा दिया तथा विकास को ही प्राथमिकता दी। विगत लगभग दो दशकों में जिस प्रकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के सभी वर्गों के लिए बिना किसी पक्षपात के कार्य किया है, उससे जनता के मध्य एक सकारात्मक संदेश गया है। विपक्षी दल आरंभ से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में विष घोलने का कार्य करते आए हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी विशेषकर नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। किन्तु जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना अपार जनसमर्थन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसाधारण का विश्वास, समर्थन एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ।

परिणामस्वरूप जनता ने केंद्र की कांग्रेस सरकार को सत्ता विहीन करके भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की बागडौर सौंप दी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तथा उन्होंने जनकल्याण के कार्यों की गंगा प्रवाहित कर दी। इसका परिणाम भी उत्साहजनक रहा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सराहनीय बहुमत दिलाया। इस बार भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने जनकल्याण के कार्यों की गति को और अधिक तीव्र कर दिया। उनके कार्यों की देश ही नहीं, अपितु विश्वभर में सराहना होने लगी।

विगत मई में अपने कार्यकाल के नौ वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पुस्तिका भी जारी की थी, जिसमें सरकार द्वारा करवाए गये जनकल्याणकारी कार्यों का लेखा– जोखा था। इसके अनुसार सरकार ने देश के 80 करोड़ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करवाई। जनधन योजना के अंतर्गत लोगों के 48.27 करोड़ खाते खोलकर उन्हें वित्तीय सेवाओं से जोड़ा गया। सुखद बात है कि इनमें से लगभग 26.54 करोड़ खाते महिलाओं के खोले गए। इस प्रकार महिलाओं

को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त 133 करोड़ लोगों के आधार को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से जोड़ा गया था तथा उन्हें लगभग 25 लाख करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई।

बेघर लोगों के लिए ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ आवासों का निर्माण करवाया गया। विशेष बात यह है कि इन आवासों में से लगभग 70 प्रतिशत में महिलाओं का नाम है अर्थात किसी में वे स्वयं स्वामी हैं तथा किसी में उनकी भागीदारी संयुक्त रूप से सम्मिलित है। इससे महिलाओं को सम्मान मिला तथा उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। अब वे केवल घर की लक्ष्मी ही नहीं हैं, अपितु स्वामी भी हैं। महिलाओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण करवाया गया। इसके अतिरिक्त 6.5 करोड़ सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया। इस प्रकार देशभर के 4335 कस्बों एवं ग्रामों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई गई।

महिलाओं के स्वास्थ्य के दृष्टिगत उन्हें चूल्हे के धुंए से छुटकारा दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए। विगत मार्च में सरकार ने सिलेंडर पर 200 रुपये का अनुदान एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। पूर्व में महिलाओं को दूर से जल लाना पड़ता था, इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 8.67 करोड़ घरों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करवाई गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 69 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित किया गया। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में गैर–कृषि क्षेत्र में लगे आय सृजित करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को दस लाख रुपये तक के सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।

मोदी सरकार ने कृषकों के कल्याण के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। देशभर के 11.39 करोड़ छोटे कृषकों को प्रधानमंत्री किसान निधि के माध्यम से प्रत्येक वर्ष छह हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही 37.59 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इसमें प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट होने पर सरकार द्वारा किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 1.37 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए विशेष पग उठाए, जिसके परिणामस्वरूप युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सका। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 से जनवरी 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने अभियान चलाया। लगभग 4.78 करोड़ नए सदस्यों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सदस्यता ली। स्टार्ट अप इंडिया के अंतर्गत 10.1 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा किए गए। सरकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के माध्यम से आगामी पांच वर्षों में 60 लाख रोजगार सृजन करने की योजना बना रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इस समयावधि में आईटीआई की संख्या 11847 से बढ़ाकर 14955 की गई। देश में 390 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जनकल्याणकारी कार्य किए हैं। इससे पूर्व देश में एम्स की संख्या केवल आठ थी, जबकि आज 23 एम्स हैं। चिकित्सीय महाविद्यालयों की संख्या भी बढ़ाई गई। पूर्व में 641 चिकित्सीय महाविद्यालय थे, जबकि अब इनकी संख्या 1341 है। इसके अतिरिक चिकित्सीय सीटों की संख्या 82466 से बढ़ाकर 152129 कर दी गई, जिससे कि अधिक छात्र प्रवेश ले सकें। इसके अतिरिक टीकारण अभियान चलाकर 220 करोड़ लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इसके साथ ही कोरोना काल के दौरान विदेशों से भारतीयों को स्वदेश लाया गया। इस दौरान लोगों को निःशुल्क राशन वितरण भी सुनिश्चित किया गया।

परिवहन एवं यातायात के साधनों का भी विकास किया गया। सरकार द्वारा 13 वंदे भारत रेलें प्रारंभ की गई हैं। आगामी तीन वर्षों में 400 स्वदेश निर्मित ट्रेनें इसमें सम्मिलित करने का कार्य जारी है। मोदी के शासनकाल में देश ने लगभग सभी क्षेत्रों में उन्नति की है। इनमें प्रमुख रूप से अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, तीन तलाक को अवैध घोषित करते हुए इस पर प्रतिबंध लगाना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना आदि सम्मिलित हैं।

जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उनके सामने अनेक चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी थीं। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के लिए चुनौतियों का सामना करते हुए विकास के पहिये को आगे बढ़ाना सरल कोई कार्य नहीं था। किन्तु उन्होंने चुनौतियों का धैर्यपूर्वक सामना किया। उनका परिश्रम रंग लाया तथा उन्हें सफलता मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्ययोजना का आधार सिद्ध करता है कि उनके पास दूरदृष्टि ही नहीं, अपितु स्पष्ट दृष्टि भी है, तभी तो देश प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर उन्नति कर रहा है।

भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुए कार्यों से अत्यधिक उत्साहित दिखाई दे रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी संगठन अपनी रणनीति पर गंभीरता से कार्य कर रहा है। पार्टी नेताओं को पूर्ण आशा है कि केंद्र में तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनेगी। इसलिए चुनाव आचार संहिता लागू होने से पूर्व ही सरकार जल कल्याण की अनेक योजनाओं को लागू करने पर बल दे रही है।

निःसंदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुशासन के माध्यम से देश को एक विकसित एवं शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित कर रहे हैं।

लेखक – लखनऊ विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है।

विकसित भारत संकल्प यात्राः भारतीय समृद्धि की ओर

हमारा देश भारतएक ऐतिहासिक देश है जो कि अपने संस्कृति, सभ्यता,विविधता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जब से सत्ता में आए है, तब से हमारा देश भारत सफलता व कीर्तिमानों के नित नए आयामों को अपने पहलुओं में संजोता जा रहा है।जहाँ वैश्विक स्तर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा व अन्तरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में निरंतर देश प्रगति की ओर अग्रसर है वहीं आमजन तक उज्ज्वला, हर घर जल, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम, अंत्योदय अन्न योज़ना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं को पहुँचा कर लाभान्वित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के माध्यम से आम जनमानस को उनके सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागृत करने का कार्य भी भारत सरकार कर रही है।

युवाओं के समक्ष स्व–रोजगार के माध्यम उपलब्ध करवाने के क्रम में उनके कौशल विकास के प्रशिक्षण के साथ ही स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योज़ना व स्टैंड–अप इंडिया जैसे योजनाओं द्वारा रोजगार हेतु अल्प दरों पर ऋण को उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों हेतु सम्मान निधि, कृषि सिंचाई योज़ना, आयुष्मान सहकार योज़ना, दीनदयाल ग्रामीण कौशल योज़ना, मत्स्य सम्पदा, वन–धन योज़ना, एपीकल्चर, सेरीकल्चर आदि योजनाओं के माध्यम से आय को दुगनी करने की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

ऐसे ही अनेकों योजनाओ द्वारा समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ भारत सरकार व प्रदेश सरकार के द्वारा चलायी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तम्भ डॉ. श्यामा प्रसाद जी व प. दीनदयाल उपाध्याय जी का स्वपन था कि भाजपा संगठन समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच कर राष्ट्रवाद के साथ सामाजिक समरसता को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग प्रदान करे। इस परिकल्पना अथवा दूरदृष्टिता को अंत्योदय का नाम दिया गया जिसे वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मा. श्री नरेंद्र भाई मोदी तथा उत्तर प्रदेश में मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महराज साकार करने में निरंतर प्रगतिशील है।

इन योजनाओं का शत–प्रतिशत क्रियान्वयन हो ऐसी मंशा के साथ योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु गत 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश के कोने–कोने में लोगों को केंद्र सरकार योजनाओं के बारे में बताना और उसका लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। यहाँ यह बताना अपरिहार्य है कि झारखंड की खूँटी लोकसभा एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ के सांसद माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी भारत सरकार में जनजाति कार्य मंत्री भी है। प्रधानमंत्री जी द्वारा ऐसे क्षेत्र से यात्रा का शुभारंभ करना जनजाति समाज के विकास के प्रति उनकी कटिबद्धता को सारगर्भित करता है। इस शुभारंभ के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि यह उनकी सरकार है जिसने गरीबों, किसानों, छोटे व्यापारियों और समाज के विभिन्न वर्गों की मदद की है। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक विकास का लाभ कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित था। लेकिन उनकी सरकार छोटे शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इससे विकसित भारत की नींव मजबूत होगी। इस अभियान में प्रचार वाहनों (मोदी सरकार के गारंटी की गाड़ी) के द्वारा शहरों के साथ ग्रामीण आँचल में गहन प्रचार किया जा रहा है। इस यात्रा का एक अहम हिस्सा है सामाजिक समृद्धि और जनहितैषी योजनाएंजिसमें महिलाओं के उत्थान, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, गरीबी को हटाने की योजनाएं सम्मिलित हैं।विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐसी पहल है जो देश के विकास और समृद्धि को भारत राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे इस उद्देश्य हेतु बनाई गयी है चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण।विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा निम्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार ग्रामसभाओं में कैंप लगाकर किया जा रहा है:–

- आयुष्मान भारत (PMJAY) – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना – खाद्य एवं नागरिक विपणन मंत्रालय
- दीनदयाल अंत्योदय योजना – ग्रामीण विकास मंत्रालय
- पीएम आवास योजना (ग्रामीण) – ग्रामीण विकास मंत्रालय
- पीएम उज्ज्वला योजना – पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- पीएम विश्वकर्मा योजना – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय
- पीएम किसान सम्मान निधि – कृषि एवं किसान विकास विभाग
- किसान क्रेडिट कार्ड – मत्स्य विभाग,कृषि एवं किसान विकास विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग
- पोषण अभियान – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

- हर घर जल (जल जीवन मिशन) – पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
- स्वामित्व योजना – पंचायती राज मंत्रालय
- जन धन योजना – वित्तीय सेवा विभाग
- पीएम प्रमाण योजना – उर्वरक विभाग
- नैनो उर्वरक प्रचार – उर्वरक विभाग

इन जनकल्याणकारी योजनाओं को जन–जन तक पहुँचाना मंत्रालयों, विभागों के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा पार्टी का भी परम लक्ष्य है, तथा यह लक्ष्य निःसंदेह भारत के आम जनमानस के विकास व समृद्धि के साथ ही भारत को वैश्विक पटल पर समृद्धि व विकासशील देश से विकसित राष्ट्र के रूप में शीर्ष पर स्थापित करेगा। चूंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा भारतसरकार,जनप्रतिनिधियों व जनता के संयोजन से चल रही है अतः यह केवल राजनीतिक या सरकारी योजना मात्र न होकर वरन एक राष्ट्रीय संकल्प है जो हर व्यक्ति को जोड़ता है और समृद्धि की दिशा में एक साझा उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करता है।इस यात्रा में सफलता पाने के लिए सभी स्तरों पर सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। सरकार, व्यापारी, समाज, और व्यक्तिगत स्तर पर भी इसमें भागीदारी करनी चाहिए।भारत राष्ट्र को एक विकसित, सशक्त व संघर्षशील देश के रूप में प्रतिस्थापित करना भी इस यात्रा का एक उद्देश्य है। यह यात्रा हमारे देश के भविष्य की दिशा में एक नई परिभाषा देती है, जहां सबका साथ, सबका विकास है, सबका विश्वास का संकल्प सबके प्रयासों से होता नज़र आता है। इस अभियान के अंतर्गत निम्न उद्देश्यों के केन्द्रित किया गया है :–

- वंचितों तक पहुंचना– उन कमजोर लोगों तक पहुंचना जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं लेकिन अभी तक लाभ नहीं उठाया है।
- योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार और जागरूकता पैदा करना।
- नागरिकों से सीखना– सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ उनकी व्यक्तिगत कहानियों/अनुभव साझा करने के माध्यम से बातचीत।
- यात्रा के दौरान सुनिश्चित विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन।

उपरोक्त बिन्दुओं को निहित करते हुये भारत सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की सक्रिय भागीदारी के साथ संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाकर चलाया गया है। देश के नागरिकों के लाभ के लिए और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सभी संबंधित पक्षों की यथासंभव व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संगठन और सरकार ने व्यापक अभियान चलाकर जनसाधारण के मध्य प्रचार का काम किया है।

इस अभियान के क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस माह 16 दिसंबर, 2023 को सायं 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से ई–संवाद किया। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया तथा पाँच राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' को झंडी दिखाकर रथ को रवाना भी किया। देश भर से हजारों लाभार्थी तथा बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि भी 'विकसित भारत संकल्प यात्रा में सम्मिलित हुये। प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर बताया कि 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' देश भर में निकाली जा रही है जिसका उद्देश्यत सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है और इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे।

सोशल मीडिया के माध्यम से भी कार्यकर्ताओं व अन्य सभी लोगों को इस अभियान में जोड़ा जा रहा है। नमो एप व viksitbharatsankalp.gov.in वेबसाइट पर "बदलते भारत की बात" नामक mikxe (module) में लाभार्थी अपने अनुभवों को वीडियो के द्वारा साझा कर सकते है है। वहीं **"विकसित भारत क्विज़"** (प्रश्नोत्तरी) में समसामयिकी आधारित 10 प्रश्नों के उत्तर देकर प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र को प्राप्त कर सकते है। अभियान में जो भी गतिविधियां लोग कर रहे है उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करने के भी विभिन्न उपकरण उपरोक्त वेबसाइट व एप उपलब्ध है जिससे की उन सोशल मीडिया उपभोक्ताओं के मित्र व पारिवारिक समूहों में उनके गतिविधियों को प्रचारित–प्रसारित किया जा सकें।

- इस अभियान का एक अहम पड़ाव है पंच–शपथ, जिसमें निम्न पाँच शपथों को स्वयं लेना है व समूहिक रूप से अन्य लोगों को भी लेने के लिए प्रेरित करना हैः–
- भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे।
- गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेकेंगे।
- देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे।
- भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे।
- नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्ति तक तक पहुँचने के क्रम में यह आलेख लिखे जाने तक 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 782 जिलों के 2431 शहरी व 86021 ग्रामसभाओं में इस अब अभियान को पहुंचाया गया है। आशा है ऐसे ही यह मोदी सरकार के गारंटी की गाड़ी देश के प्रत्येक ग्राम तक पहुँचे व सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिले व 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनें व श्री नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनें।

अटल जी का भारतीय अर्थायाम्

डॉ0 हरनाम सिंह

सशक्त –समृद्ध विकसित और स्वाभिमानी राष्ट्र के स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रखने में अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन मॉडल का महत्वपूर्ण योगदान है। अटल जी के आर्थिक फैसलों से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली। अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भारत को महाशक्ति बनाने का जो मार्ग प्रसस्त किया था वर्तमान सरकार की मौद्रिक आर्थिक प्रबंधन उसी मार्ग पर अग्रसर है। अर्थव्यवस्था की धड़कन देश की सड़कों उन सड़कों पर निर्भर करती है जो उसकी धमनियों का काम करती हैं । निर्माण और बुनियादी ढांचे की उन्नति आर्थिक विकास के अग्रदूत के रूप में कार्य करती है। अटल जी की आर्थिक विकास की परिकल्पना सदैव औधोगिक विकास सामाजिक विकास एवं कृषि विकास के इर्द–गिर्द ही रहती थी। उनकी आर्थिक नीतियों ने हर वर्ग को प्रभावित किया और एक बड़ी शोषित और वंचित आबादी को आर्थिक मजबूती प्रदान किया। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "भारतमाला एवं सागरमाला" योजना अटलजी के स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से प्रभावित दिखती है। अटल जी की आर्थिक सोच में भारत की आर्थिक समृद्धि झलकती थी। जिस जीएसटी को लेकर आज हम "एक देश एक कर" के रूप में चर्चा करते हैं वह अटल जी की ही परिकल्पना थी। उन्होंने ही सबसे पहले एक देश एक कर का स्वप्न देखा था।

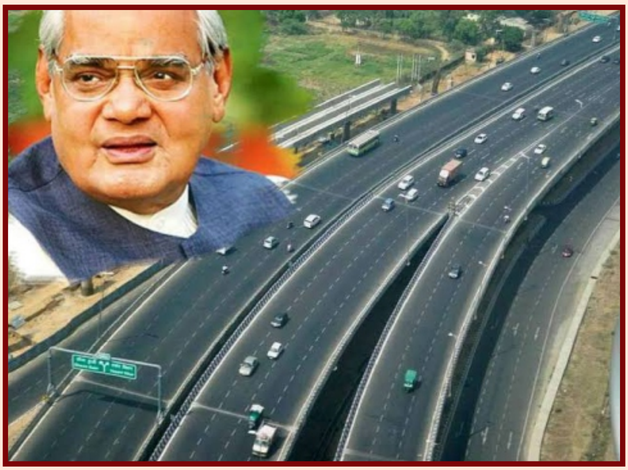

भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है जहाँ आर्थिक चिंतन की भी सुदीर्घ परंपरा रही है। तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी लोकप्रिय राजनेता के साथ कुशल प्रशासक थे। आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिनसे देश की दशा और दिशा बदली है । आर्थिक उदारवाद की नीति के बाद अटल जी आर्थिक विकास के एक स्तंभ के रूप में उभरे थे । स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के जरिए भारत की सांस्कृतिक एवं आर्थिक दूरी को कम करने का कार्य किया था। 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था नई उड़ान की तरफ अग्रसर हुई और आगे चलकर इस उड़ान के अगुवा बने थे अटल बिहारी वाजपेई। संभावना जताई जा रही थी कि संघ की पृष्ठभूमि से आया हुआ नेता अर्थव्यवस्था में खुले मंच की वकालत कैसे करेगा। संघ तो स्वदेशी आंदोलन की बात करता है। सन् 1991 की उदार आर्थिक नीति के समय भी स्वदेशी जागरण मंच ने इसका भरपूर विरोध किया था। इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेई की आर्थिक नीतियों ने भारत को खुले बाजार में उड़ना भी सिखाया और मजबूती से टिकना भी । उनकी आर्थिक सोच में भारत की आर्थिक समृद्धि झलकती थी। जिस जीएसटी को लेकर आज हम "एक देश एक कर" के रूप में चर्चा करते हैं वह अटल जी की ही परिकल्पना थी। उन्होंने ही सबसे पहले एक देश एक कर का स्वप्न देखा था। सन 1991 में नरसिम्हाराव सरकार के दौरान शुरू किए गए आर्थिक सुधारों को उन्होंने आगे बढ़ाया। 2004 में जब वाजपेयी ने मनमोहन सिंह को सत्ता सौंपी तब अर्थव्यवस्था की तस्वीर बेहद खूबसूरत थी। जीडीपी ग्रोथ रेट 8 फीसदी से अधिक और महंगाई दर 4 फीसदी से कम थी। विनिवेश और निजीकरण के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया और जिम्मेदारी अरुण शौरी को सौंपी थी।

अटल बिहारी वाजपेयी और सुशासन

सुशासन का विकास से अभिन्न संबंध है। सुशासन के बिना विकास की अवधारणा को साकार करना संभव नहीं है। आचार्य कौटिल्य ने अपनी प्रख्यात पुस्तक अर्थशास्त्र में सुशासन को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रजा का हित ही राजा का परम लक्ष्य है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है। भारत रत्न अटल जी के जन्मदिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सुशासन की महत्ता को रेखांकित करते हुए सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि सुशासन किसी भी राष्ट्र की प्रगति की कुंजी होती है। महात्मा गांधी जी ने जिस रामराज्य की संकल्पना की थी उसमें सुशासन ही सुराज के रूप में अवतरित हुआ है। वहीं लोकमान्य तिलक के शब्दों में देश में स्वराज्य ही नहीं सुराज भी आना चाहिये। सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत डॉ. अम्बेडकर की सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणा मानवाधिकारों की सुरक्षा की गांरटी के बिना कैसे सुशासन की परिकल्पना को साकार कर

सकती है । एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के अर्थात अन्त्योदय की संकल्पना भी सुशासन की अवधारणा में ही निहित है। अटलजी ने राजनीति में नैतिक मूल्यों आदर्शों की पवित्रता को अक्षुण्ण रखते हुए सुशासन की बुनियाद रखी ताकि जवाबदेह उत्तरदायी पारदर्शी प्रभावशाली न्याय संगत कुशल एवं समावेशी शासन व्यवस्था को साकार किया जा सके।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

अटलजी के दूरदर्शी नेतृत्व में आम आदमी के कल्याण के लिए 'अन्त्योदय अन्न योजना' प्रारंभ हुई ताकि गरीबों को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध हो सके । किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना लागू कर भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को नये क्रांतिकारी आयाम दिये। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से प्रत्येक पंचायत को जोड़ने की सड़क क्रांति भारतीय अर्थव्यवस्था की अधोसंरचना के निर्माण में मील का पत्थर सिध्द हुई है। स्वर्णिम चतुर्भुज राज मार्गों का विराट नेटवर्क चैन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुम्बई जैसे महानगरों को आपस में जोड़ता है जो आर्थिक विकास की संभावनाओं को साकार रूप प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भारत की आत्मा को स्पर्श करती हुई उन दूरस्थ ग्रामीण अंचलों को जोड़ती है जो संपर्क सड़कें न होने से विकास की मुख्य धारा से कटे हुए थे। इसका सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण जनजीवन का सशक्तिकरण हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां मिली उपज समय पर कृषि उपज मंडियों तक पहुंचने से किसानों का सशक्तिकरण हुआ।

आर्थिक सुधार और अटल विहारी वाजपेयी

अटल जी के नेतृत्व में भारत में आर्थिक सुधारों के एक नये युग का सूत्रपात हुआ। वर्ष 1998 से 2004 तक आर्थिक वृध्दि के मोर्चे पर आर्थिक मंदी के बावजूद हमारी सकल घरेलू उत्पाद दर में आठ प्रतिशत की वृध्दि दर्ज हुई। विदेशी मुद्रा भंडार में भी अभूतपूर्व वृध्दि हुई जो 1998 में मात्र 12 अरब डालर से बढ़कर 102 अरब डालर तक पहुंचा और हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था का द्योतक बना। वित्तीय घाटे को कम करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम लागू किया। वहीं दूसरी ओर व्यवसायों और उद्योगों के संचालन में सरकारी भूमिका सीमित करने उनकी प्रतिबध्दता देश में एक पृथक विनिवेश मंत्रालय गठित किये जाने से परिलक्षित होती है। उल्लेखनीय है कि उनके कार्यकाल में महंगाई दर चार प्रतिशत तक ही सीमित रही। "रणनीतिक बिक्री" के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण का साहसी निर्णय लिया था। आपके कार्यकाल में भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड जैसी कंपनियों का विनिवेश देखा गया। अटल जी की दूरदर्शिता के चलते ही आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जा रही है। परमाणु परीक्षण के समय विकसित राष्ट्रों के आर्थिक बहिष्कार की धमकी के सामने झुकने से इनकार करते हुए उनका कवि हृदय कह उठता है– "बाधाएं आती हैं आयें, घिरे प्रलय की घोर घटायें, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालायें, निज हाथों में हंसते–हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।"

अटल बिहारी वाजपेयी और दूरसंचार

अटल जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 3 मार्च 1999 को नई दूरसंचार नीति की घोषणा की । इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया। कारोबार और उद्योग चलाने में सरकारी भूमिका को कम करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। दूरसंचार जो एक स्थिर और मंद उद्योग बन गया था उसे बढ़ावा दिया। यह बाजपेयी की नीति थी जिसने भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना दिया और आने वाले वर्षों में चीन से आगे निकलने के लिए तैयार है। नई दूरसंचार नीति ने सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियों के आधिपत्य को समाप्त कर दिया और दूरसंचार क्रांति की शुरुआत करने वाली निजी कंपनियों की भागीदारी को उत्प्रेरित किया। निजी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण टैरिफ में काफी गिरावट आई और दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में भी भारी सुधार हुआ। नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने अपनी किताब में लिखा है कि वाजपेयी जी की टेलिकाम सेक्टर को लेकर लिए गए फैसले ने ही भारतीय टेलिकाम सेक्टर की नंइ इबारत लिखी। वाजपेयी सरकार द्वारा लाइ गंइ नंइ टेलिकाम नीति ने ही देश में टेलिकाम पेनीट्रेशन का बड़े स्तर पर प्रभावी बनाया।

आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण

प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी का सम्पूर्ण कार्यकाल आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोकतंत्र को

सार्थक और जीवंत बनाये रखने के लिये प्रतिबध्द था। वे समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए सर्वाधिक उपेक्षित के सशक्तिकरण को सुशासन की आवश्यक शर्त मानते थे। अपने कार्यकाल के कार्यों का निष्पादन उन्होंने एक मजबूत विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने अधिकतम सामाजिक अवसरों को सृजित करने लोकतंत्र की परम्पराओं को संरक्षित सुरक्षित करने जनता की सक्रियता और भागीदारी बढ़ाने के साथ 'नागरिक प्रथम' के महती सिध्दांत पर चलकर आम नागरिकों के कल्याण तथा आम नागरिक के शासन से जुड़ाव पर केंद्रित रखा।

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट -आर्थिक विकास

इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अटल जी ने दो महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पहली परियोजना गोल्डेन क्वाड्रिलेटरल के जरिए देश के चार महानगरों को जोड़ने के लिए नेशनल हाइवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। दूसरी परियोजना देश के सभी ग्रामीण इलाकों को जोड़ने को लेकर था जिसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था । इन दोनों परियोजनाओं ने देश के रियल एस्टेट सेक्टर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। जिससे आगे चलकर भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण रहीं। नीतिगत निर्णयों में से एक 2003 के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम की शुरूआत थी जिसने सरकारी खर्च में अनुशासन लाने और राजकोषीय शुद्धता पर फोकस था। ऐसी आर्थिक नीतियां जिन पर अटल जी के व्यक्तित्व की छाप देखी जा सकती है। उन्हीं के विचारों से प्रभावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहतें है कि जब अटल जी बोलते तो लगता कि देश बोल रहा है। उनके द्वारा उठाये गए आर्थिक सुधार है :

1. स्वर्णिम चतुर्भुज और ग्राम सड़क योजना

वाजपेयी जी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में उनकी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सबसे ऊपर रखा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने चेन्नैइ कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को हाईवे नेटवर्क से कनेक्ट किया । जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए गांवों को पक्की सड़कों के जरिए शहरों से जोड़ा गया। ये योजनाएं सफल रहीं और देश के आर्थिक विकास में मदद मिली।

2. निजीकरण

अटल विहारी वाजपेयी ने बिजनस और इंडस्ट्री में सरकार की भूमिका कम की। इसके लिए उन्होंने अलग से विनिवेश मंत्रालय बनाया। सबसे महत्वपूर्ण फैसला भारत ऐल्युमिनियम कंपनी हिंदुस्तान जिंक इंडिया पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विनिवेश का था। वाजपेयी के इन पहलों से भविष्य में सरकार की भूमिका तय हो गई।

3. राजकोषीय जवाबदेही

वाजपेयी सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए राजकोषीय जवाबदेही ऐक्ट बनाया। इससे सार्वजनिक क्षेत्र बचत में मजबूती आई और वित्त वर्ष 2000 में जीडीपी के –0.8 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 2005 में 2.3 फीसदी तक पहुंच गई।

4. सर्व शिक्षा अभियान

शिक्षा के क्षेत्र में अटल जी का योगदान सर्व शिक्षा अभियान के रूप में भी मील का पत्थर साबित हुआ जो कि 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने की सामाजिक योजना है। सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत के चार वर्षों के भीतर स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में 60 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

5. टेलिकॉम क्रांति

वाजपेयी सरकार अपनी नई टेलिकॉम पॉलिसी के तहत टेलिकॉम फर्म्स के लिए एक तय लाइसेंस फीस हटाकर रेवन्यू शेयरिंग की व्यवस्था लेकर लाई थी। भारत संचार निगम का गठन भी पॉलिसी बनाने और सर्विस के प्रविशन को अलग करने के लिए इस दौरान किया गया था। वाजपेयी की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय टेलिफोनी में विदेश संचार निगम लिमिटेड के एकाधिकार को पूरी तरह खत्म कर दिया था।

अटलजी का समग्र जीवन राष्ट्र की सेवा के लिये समर्पित रहा। भारतीय आर्थिक मूल्यों एवं सकारात्मक चिंतन के धनी वे अद्भूत व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी आभा से न केवल भारत की प्रतिष्ठा एवं गौरव में श्रीवृध्दि की वरन् देश को आर्थिक सुशासन का अनूठा संबल प्रदान कर विकास को एक नई दिशा प्रदान की। वे सुशासन की एक ऐसी विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उन्नयन के प्रति प्रतिबध्द होकर देश की उन्नति में सामान्यजन अपनी भागीदारी की सुखद अहसास कर सके। उनकी सरकार ने औद्योगिक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों, सूचना प्रौद्योगिकी और औद्योगिक पार्को की स्थापना शुरू की और सही मायनो में मेक इन इंडिया की नींव का नेतृत्व किया। आपके शासन ने अपने साहसिक सुधारों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ी और बुनियादी ढांचे के विकास के एक नए युग की शुरुआत की। आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक विकास की नींव रखी। आपका सन्देश था कि हमें नया भारत नहीं बनाना पर इस प्राचीन देश को आधुनिक समय की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। आप ने देश को विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए आर्थिक विकास एवं सुशासन के नए प्रतिमान स्थापित किए।

लेखक सहायक आचार्य अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

"अन्त्योदय" के प्रणेता अटल बिहारी वाजपेयी

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर

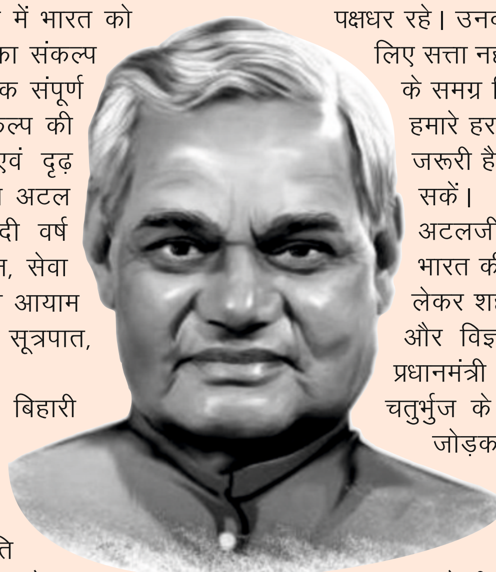

प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी 25 वर्ष में भारत को वैभव के उस शिखर पर पहुंचाने का संकल्प लिया है, जहां से भारत का आलोक संपूर्ण विश्व में पहुंचे। हम सभी इस संकल्प की सिद्धि के लिए कृत संकल्पित एवं दृढ़ निश्चयी हैं। दो वर्ष बाद जब हम अटल बिहारी वाजेपयी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाएंगे, उसके पहले हमें सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण की दिशा में वे आयाम स्थापित करने होंगे, जिनका सूत्रपात, अटलजी ने किया था।

भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की २५ दिसंबर को 99वीं जन्म जयंती है। दो वर्ष बाद हम सभी उनका जन्मशती वर्ष मनाएंगे। वाजपेयी वस्तुतः भारत की राजनीति में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और पारदर्शिता के सिद्धांत को पुनर्स्थापित करने वाले राष्ट्रनायक थे। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विकास के नवीन आयाम स्थापित किए हैं। अटलजी सिर्फ राष्ट्र नायक ही नहीं थे, वे जन नायक भी थे। वे भारत की करोड़ों–करोड़ जनता के हृदय पर राज करते थे। अटलजी के सिद्धांतों की उंगली पकड़ कर राष्ट्रसेवा की राह पर चलने वालों की एक पीढ़ी भारत में है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यों में उन्हीं की वाणी की अनुगूंज सुनाई देती है।

अटलजी राजनीति के ऐसे अजातशत्रु थे, जिन्होंने पक्ष–विपक्ष से ऊपर उठकर समभाव और सामंजस्य की एक नई मिसाल बनाई थी। उनका ध्येय वाक्य ही था कि 'छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता'। वे विपक्षी दलों को भी साथ लेकर चलने की कला जानते थे। अपने बड़े मन की उदारता के बल पर ही विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता पक्ष के नेताओं से ज्यादा वे देश में लोकप्रिय हुए। 1994 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में पाकिस्तान द्वारा मानवाधिकार हनन के लगाए गए झूठे आरोपों का जवाब देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा भेजे गए दल का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। अटलजी तब विपक्ष के नेता थे और उन्होंने दलों की दहलीज से ऊपर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से भारत की ओर से सशक्त जवाब पेश किया था। पाकिस्तान ने बाद में अपना प्रस्ताव वापस ले लिया था और भारत की जीत हुई थी। अटलजी सदैव राजनीति में शुचिता और सुशासन के प्रबल पक्षधर रहे। उनका कहना था कि हमें सुख भोगने के लिए सत्ता नहीं मिली है, यह जनकल्याण और राष्ट्र के समग्र विकास की जिम्मेदारी का दायित्व है। हमारे हर काम में पूर्ण पारदर्शिता और शुचिता जरूरी है, ताकि हम सुशासन को स्थापित कर सकें।

अटलजी ने प्रधानमंत्री रहते हुए भविष्य के भारत की एक ऐसी नींव रखी, जिसमें गांव से लेकर शहर तक और किसान से लेकर जवान और विज्ञान तक का अद्भुत समन्वय था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर स्वर्णिम चतुर्भुज के माध्यम से देश को सड़क मार्ग से जोड़कर विकास को नई गति देना अटलजी का ही दूरदर्शी कदम था। देश में कृषि क्षेत्र में सुधार की आधारशिला अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही रखी गई। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुचिता, सुशासन और गरीब कल्याण का एक नया अध्याय भारत के इतिहास में लिखा जा रहा है, जिसकी भूमिका अटलजी ने लिखी थी। हर नागरिक का बैंक खाता, हितग्राहियों को सरकार की योजना के लाभ का सीधे बैंक खाते में अंतरण, संचार प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल क्रांति के माध्यम से सरकार के प्रत्येक कार्य में पूर्ण पारदर्शिता ऐसे कदम हैं, जो सरकार की नीयत में शुचिता एवं जनसेवा की शुद्धता को सुस्थापित करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, हर घर नल जल, उज्ज्वला योजना जैसे सैकड़ों कदम हैं, जो गरीब कल्याण की दिशा में अटलजी की ही बताई हुई राह में सरकार ने उठाए हैं। अटलजी कृषि क्षेत्र में सुधार के प्रबल पक्षधर थे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को सशक्त करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री फसल बीमा, कृषक उत्पादक संगठन, पीएम किसान सम्मान निधि, उत्पादन के साथ फसल विविधीकरण पर जोर दिया गया है। स्वतंत्रता का अमृत काल प्रारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री ने आगामी 25 वर्ष में भारत को वैभव के उस शिखर पर पहुंचाने का संकल्प लिया है, जहां से भारत का आलोक संपूर्ण विश्व में पहुंचे। हम सभी इस संकल्प की सिद्धि के लिए कृत संकल्पित एवं दृढ़ निश्चयी हैं। दो वर्ष बाद जब हम अटल बिहारी वाजेपयी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाएंगे, उसके पहले हमें सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण की दिशा में वे आयाम स्थापित करने होंगे, जिनका सूत्रपात, अटलजी ने किया था।

'नया भारत' नेतृत्व नीति और नीयत का परिणाम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 साल के कार्यकाल में नए भारत का दर्शन हो रहा है और इस नए भारत का प्रतिबिंब युवाओं में दिख रहा है। मोदी जी के नेतृत्व, उनकी नीति और नीयत का ही परिणाम है कि खेल की हर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत के खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं।

कांग्रेस मोदी हटाओ–मोदी हटाओ के नारे लगाती है लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कहते हैं कि देश को आगे बढ़ाओ और विकास की ओर आगे ले जाओ। मैं देश की जनता से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को 2024 के चुनाव में करारा सबक सिखाएं।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह, बस्ती से भाजपा सांसद श्री हरीश द्विवेदी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ अधिकारी और नेता उपस्थित रहे। उन्होंने जनता को कांग्रेस शासन के दौरान देश में रही खिलाड़ियों दुर्दशा के बारे विस्तार से चर्चा की। साथ ही, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए किए गए कार्यों से अवगत कराया। अपने संबोधन में उन्होंने देश के उप–राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी को अपमानित करने के लिए विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा।

श्री नड्डा ने संसद में विपक्षी नेताओं द्वारा देश के उप–राष्ट्रपति राज्य सभा सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी के अपमान किए जाने पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता संसद में अपने नेता को वाद विवाद करने और जनता के मुद्दे उठाने के लिए भेजती है लेकिन जो विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, वे वाद–विवाद के बदले जोकर बनने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के नेता जोकर की तरह नकल करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के एक सांसद द्वारा संवैधानिक पद पर बैठे भारत के उप–राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति की संसद भवन प्रांगन में नकल की गई, घमंडिया गठबंधन के नेता ठहाके लगाते रहे और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहे। ये कितनी शर्मनाक बात है! श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास 100 साल से ज्यादा का है, जब उसका नेता एक नकलची का वीडियो बनाता है और संवैधानिक पद पर बैठे भारत के उप–राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, जो कि ओबीसी वर्ग से आने वाले किसान के पुत्र हैं, उन्हें अपमानित करता है। तब ऐसे समय पर ओबीसी और पिछड़े वर्ग का राग अलापने वाले राहुल गांधी को ओबीसी की याद नहीं आई? उन्होंने जनता से सवाल किया कि क्या देश के उपराष्ट्रपति को अपमानित करने वाले ऐसे लोगों को देश सहन करेगा? ऐसे लोगों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस के नेता आजकल कैमरामेन का काम संभाल रहे हैं। श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस मोदी हटाओ–मोदी हटाओ के नारे लगाती है लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कहते हैं कि देश को आगे बढ़ाओ और विकास की ओर आगे ले जाओ। मैं देश की जनता का आह्वान करता हूँ कि आप मोदी जी को हटाने वालों को 2024 में हटाकर देश का विकास करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जिताएं और आगे देश को आगे बढ़ाएं।

श्री नड्डा ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के साढ़े 9 साल के कार्यकाल में नए भारत का दर्शन हो रहा है और इस नए भारत का प्रतिबिंब हमारे युवाओं की शक्ति में भी दिख रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 साल पहले हमारे सांसद श्री हरीश द्विवेदी ने खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी और आज हर स्थान पर खेल महाकुंभ आयोजित हो रहा है। खेल महाकुंभ की शुरुआत 1 लाख विद्यार्थी और 50 हज़ार खिलाड़ियों के साथ हुई थी, जो आज

3.5 लाख खिलाड़ी और 4.5 लाख विद्यार्थी तक पहुंच गई है।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश चलाने के लिए नेतृत्व, नीति, नीयत और सही कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पहले खेल जगत में भारत का वैश्विक दबदबा नहीं रहता था। कांग्रेस के कार्यकाल के 70 वर्षों में भारत ने कभी एशियाई खेलों में अच्छी संख्या में मेडल नहीं जीते, ओलंपिक तो दूर की बात थी। मगर, पिछले एशियाई खेल में हमारे खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा मेडल जीते। आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, खेलों को अधिक प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने टोक्यो ओलंपिक समेत हर प्रतिस्पर्धा में पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा मेडल जीते हैं।

श्री नड्डा ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में खिलाड़ी बड़े शहरों से खेल क्लब के माध्यम से आते थे लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद आज खेल जगत में खिलाड़ी अब सिर्फ बड़े शहरों से नहीं बल्कि आज गांव, गरीब, कस्बे से निकलने वाला एक नौजवान भी खिलाड़ी बनता है और ओलंपिक में विजय प्राप्त करता है। यह है नीति का परिवर्तन, नेतृत्व की क्षमता, नीयत का प्रदर्शन, यही है कार्यक्रम का विश्लेषण। 2014 में कांग्रेस शासन में खेल का बजट केवल ₹1 हजार 219 करोड़ का था, लेकिन भाजपा सरकार में खेल का बजट बढाकर ₹3 हजार 397 करोड़ कर दिया गया है। 2014 के पहले कोई भी ओलंपिक पोडियम योजना नहीं थी, अब टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना बनाई गई है, जिसके माध्यम खिलाड़ियों की लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिल रही है। श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की नीति के कारण आज देश के खिलाड़ियों को विदेशी ट्रेनिंग की व्यवस्था प्रदान की जा रही है।

सम्माननीय भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज वैश्विक स्तर के खेल उपकरण भी मुहैया करा रहा है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹50 हजार प्रति महीना दिया जा रहा है। लगभग 8 हजार प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया गया है जिन्हें ओलंपिक के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें 5 हजार युवक और 3 हजार बालिकाएं हैं। साथ ही, उनके प्रशिक्षण के लिए 34 कोच और अनुशासन केंद्र भी बनाए गए हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि 'खेलो इंडिया' का कार्यक्रम ₹1000 करोड़ की निधि से 2016 में शुरू हुआ था और इसमें 2,500 खिलाड़ी चयनित हुए हैं। चयनित खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स सेंटर परिचालित किए गए हैं, जिनमें से 80 स्पोर्ट्स सेंटर उत्तर प्रदेश में परिचालित हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और खेल मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि यह तय किया गया है कि हर पंचायत और गांव स्तर पर खेल के मैदान, ओपन जिम खोले जाएंगे और अब इंडिया का बच्चा नहीं, भारत का बच्चा आगे खेलने जाएगा ताकि हम प्रतिस्पर्धा में अपना शत प्रतिशत योगदान दे सकें। चाहे टोक्यो ओलंपिक हो या एशियन गेम्स, भारत पहली बार इतने ज्यादा मेडल जीत कर लाया है और यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व, नीति, नीयत और उनके कार्यक्रम के कारण संभव हुआ है, जिसे श्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की धरती पर पूरी ताकत से लागू किया है।

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारत आज सभी क्षेत्रों में पहले स्थान पर है। स्किल इंडिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी समेत सभी स्कीम भारत को मजबूती प्रदान कर रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी, अनुसूचित जाति, महिला, युवा और किसान को ताकत प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप आज भारत मजबूती से विकास के पथ पर अग्रसर है। जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल राज किया उसको पछाड़ कर आज भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गई है। जनता के आशीर्वाद से 2024 में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और 3 साल के भीतर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह देश को आगे बढ़ाने का, मजबूत बनाने का और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का विषय है।

मातृ शक्ति सम्पूर्ण सृष्टि का आधार : ज्योति

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति पंडया तथा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीता शाक्य ने 9 विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मध्य भारत के 8 राज्यों की मोर्चा पदाधिकारी बहनों के साथ साझा किया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में उत्तर प्रदेश सहित बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ, राजस्थान एवं उडीसा की मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी सम्मिलित हुईं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद से अब तक उपेक्षित नारी शक्ति को नारी शक्ति वंदन अधिनियम से उनको नेतृत्व एवं अधिकार देने का काम किया। उन्होंने कहा कि मातृ शक्ति सम्पूर्ण सृष्टि का आधार है और भाजपा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते के सिद्धान्त के साथ सदैव नारी सम्मान तथा नारी अधिकारों की पक्षधर है। भाजपा सेवा भाव के साथ राजनीति करने में विश्वास करती है। आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओ का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है और आधी आबादी की आत्मनिर्भरता के साथ ही भारत की आत्मनिर्भरता का संकल्प भी पूर्ण होगा।

महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति पंडया ने कहा कि नारी शक्ति को भाजपा के साथ जोड़ने के लिए विशेष अभियान पार्टी द्वारा तय किये गए है। विभिन्न क्षेत्रों में सभी प्रभावी मातृशक्तियों को सम्पर्क के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का कार्य महिला मोर्चा करेगा। उन्होंने कहा कि एनजीओ से जुड़ी हुई महिलाएं, खेलकूद से जुड़ी हुई महिलाएं, प्रबुद्ध वर्ग की महिलाएं, ट्रांसजेण्डर, महिला साहित्यकार, महिला पत्रकार, स्वयं सहायता समूह संचालित करने वाली महिलाओं, नव युवतियों आदि से अभियान चलाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा तथा भाजपा सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़ने का कार्य करेगी।

प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि नारी शक्ति के भाजपा नेतृत्व पर लगातार विश्वास से ही भाजपा को लगातार सफलता का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आधी आबादी से संवाद तथा उनके विचारों को जानने के लिए महिला मोर्चा ही एक मात्र माध्यम है। महिला मोर्चा विभिन्न अभियानों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जनकल्याणकारी एवं महिला कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेकर पहुंचे। महिलाओं की सरकार तथा संगठन से अपेक्षायें संगठन तक पहुंचाने में आप सभी बड़ा माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में महिला मोर्चा के जो 9 अभियान प्रारम्भ होने वाले हैं उन सभी अभियानों में प्रदेश ईकाई प्रभावी कार्य करेगी।

महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीता शाक्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश ईकाई सभी प्रदेशों से आई हुई मोर्चा पदाधिकारियों का अभिनंदन करती है और केन्द्रीय नेतृत्व को आश्वस्त करती है कि केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा तय प्रत्येक अभियान व कार्यक्रम को सफलता से संचालित करेगी।

कार्यशाला में मोर्चा की राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों में उषा बाजपेयी, डा. कायनात काजी, आयुषी श्रीमाली, नीतू डवास, डा. ममता रानी, निशा सिंह, डा. कीर्तिका अग्रवाल, ऊषा मौर्या, पूजा मिश्रा प्रमुख रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन मोर्चा की महामंत्री रश्मि रावल ने किया।

हमारी सांस्कृतिक विरासत ही, आधुनिक विरासत की पूंजी : शाह

नई दिल्ली के बुराड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन श्री अमित शाह ने कहा कि जैसे ही उन्होंने छात्र शक्ति– राष्ट्र शक्ति का नारा सुना तो वह अपनी उम्र में 30 साल पीछे चले गये और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वह भी युवा छात्र हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन और चरित्र निर्माता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि बनकर और भाषण देते हुए उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने छात्रों को संबोधित उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत गुजरात राजकोट में एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन से हुई थी, जहां वह पंडाल में सबसे पीछे बैठे हुए थे। अमृत महोत्सव के वर्ष में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में युवाओं के साथ बातचीत बहुत ही आनंद का विषय है।

श्री अमित शाह ने कहा कि यह अधिवेशन दो दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पहला यह कि यह अधिवेशन विद्यार्थी परिषद के अमृत वर्ष में प्रवेश करने वाला है, और दूसरा यह है कि यह अधिवेशन आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। हमारे देश ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, 75 साल में देश ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है जिससे पूरा विश्व आज भारत का लोहा मान रहा है और इसके साथ ही हमने अपनी संस्कृति को संजोकर विश्व में गौरव दिलाने का प्रयास किया है। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता और विशेष तौर पर युवाओं का आव्हान किया है कि आने वाले 25 साल विश्व में भारत सर्वप्रथम और सबसे महान हो यह संकल्प लेकर इसको चरितार्थ करने के प्रति संकल्पित है। वे अपने समय में विद्यार्थी परिषद का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए सातत्यपूर्ण 75 साल की यात्रा सिर्फ छात्र संगठन कर सकता है।

छात्र युवा होते हैं, जोश से परिपूर्ण होते हैं, कई बार रास्ता भटकने की संभावनाएं होती हैं लेकिन विद्यार्थी परिषद के संगठन की व्यवस्था इतनी मजबूत और चाक चौबंद रही है कि विद्यार्थी परिषद 75 साल में न ही रास्ता भटका और न ही समाज और सरकार को रास्ता भटकने दिया। ज्ञान और एकता के अपने मूलमंत्र को आत्मसात करते हुए धैर्यपूर्वक एक पाठ का निर्माण किया। इस रास्ते में शिक्षा जगत और देश की सीमाओं के सामने जितनी भी चुनौतियां आईं। हर चुनौती के सामने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हिमालय की तरह अडिग रहकर संघर्ष किया और इसे देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा।

श्री मदन दास देवी जी को याद किया। मदन दास देवी जी ने छोटे–छोटे कार्यकर्ताओं को जीवन में रास्ता दिखाने व गलत रास्ते पर न जाए और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे इसे मार्गदर्शन देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे वरिष्ठ नेता जैसे यशवंत राव केलकर, बाला साहब आपटे, डिडोलकर जी जैसे महानपुरुषों के योगदान को को कभी भुला नहीं जा सकता है विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ नेताओं ने विद्यार्थी परिषद को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ते हुए 75 साल का प्रवास पूरा करने का श्रेय तपस्वियों को जाता है। 1949 से लेकर 2023 तक की यात्रा देश के विकास के साथ साथ जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि ढेर सारे आंदोलनों में विद्यार्थी परिषद ने 'स्व' जोड़ने का संघर्ष किया है चाहे भाषा का, शिक्षा

का, या फिर संस्कृति संस्कृति को बरकरार रखना का आंदोलन हो हर चीज में 'स्व' का महत्व विद्यार्थी परिषद ने युवाओं के माध्यम से समाज को बताया है। उन्होंने कहा कि देश का कोई भी क्षेत्र हो चाहे संशोधन का क्षेत्र हो, शिक्षा, कला, राजनीति, पत्रकारिता, इन सभी क्षेत्रों में विद्यार्थी परिषद की सुगंध हर क्षेत्र में मिलेगी। विद्यार्थी परिषद ने कई सारे प्रकल्प लिए जो वर्षों तक चले, जैसे कोई शिल्पी 75 वर्षों तक, एक प्रतिमा को गढ़ता है, ठीक इसी तरह बीते वर्षों में सभी समस्याओं के निवारण के लिए, विद्यार्थी परिषद ने पुरुषार्थ किया। भारत और चीन के युद्ध के बाद सील –प्रकल्प चालू हुआ, जो आज भी पूरी ताकत से चल रहा है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें वर्ष में आयोजित हो रहे चार–दिवसीय 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली के बुराड़ी स्थित डीडीए ग्राउंड में बसाई गई टेंट सिटी इंद्रप्रस्थ नगर के मदनदास देवी सभागार में किया गया। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन उद्घाटन के अवसर पर अमित शाह ने परिषद के थीम सॉंग और राष्ट्रीय चेतना पर आधारित 5 पुस्तकों का विमोचन भी किया।

अभाविप के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के प्रत्येक ज़िले व विश्वविद्यालय–महाविद्यालय परिसर से दस हजार से अधिक छात्रा–छात्र इस महाकुंभ का हिस्सा बनने हेतु दिल्ली के बुराड़ी स्थित डीडीए मैदान पहुँचे हैं। इस अधिवेशन में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पर आधारित 8 थीम वाली विशाल प्रदर्शनी लगायी गयी है जिसमें भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, राष्ट्रीय एकात्मता, विद्यार्थी परिषद की 75 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाया गया है, इस प्रदर्शनी को परिषद के संस्थापक सदस्य और संघ के वरिष्ठ प्रचारक स्व. दत्ताजी डिडोलकर के नाम पर समर्पित किया गया है। अधिवेशन के लिए 52 एकड़ में फैले विस्तृत परिसर में ऐतिहासिक इंद्रप्रस्थ नगर के स्वरूप में टेंट सिटी बसाई गई है,जहां देश के हर एक कोने से आये विद्यार्थी 4 दिन तक रुकेंगे।

इस वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगाँठ भी है। इसी उपलक्ष्य पर अभाविप ने गत 28 नवम्बर को महाराष्ट्र के रायगड क़िले से हिन्दवी स्वराज्य यात्रा भी शुरू की थी जो देश के 75 ज़िलों से गुजरते हुए विभिन्न स्थानों की मिट्टी कलश में एकत्रित कर 07 दिसंबर को विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन स्थल पर समाप्त हुई। अधिवेशन में कीर्तिमान स्थापित करते हुए ध्वजारोहण के उपरांत एकसाथ 8500 विद्यार्थियों और 150 दिव्यांग विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया गया। संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में स्थापित और कार्यरत अभाविप का आज विश्वव्यापी स्वरूप उसके इन्हीं 75 वर्षों के संघर्षों की तपस्या का फल है। 50,65,264 सक्रिय सदस्यता के साथ आज इसका अस्तित्व भारत के प्रत्येक शैक्षणिक परिसर में है तथा इसके साथ ही सामाजिक, पर्यावरणीय, सेवा, खेल, आदि क्षेत्रों में भी प्रभावी रूप से समाधान का विकल्प देते हुए कार्य कर रही है।

अभाविप के अमृत महोत्सव वर्ष के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे चार दशक पहले का समय याद आ रहा है जब मैं कार्यकर्ता के रूप में पिछली पंक्ति में बैठा करता था। चीन युद्ध के बाद पूर्वोत्तर को देश से जोड़े रखने का कार्य करने में परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण है। मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं विद्यार्थी परिषद का एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूँ। चाहे भाषा व शिक्षा का आंदोलन हो या संस्कृति को बरकरार रखना हो, हर क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद ने युवाओं के माध्यम से समाज को 'स्व' का महत्त्व बताया है। विश्व में भारत के बढ़ते क़द के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा यह देश के लिए जीने का समय है, युवा भारत माता को जीवन समर्पित करने के संकल्प के साथ इस अधिवेशन से लेकर जाएं और समाज को भी इस दिशा में एकजुट करें।

अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही ने कहा कि ध्येय की निष्ठा, स्थान की पवित्रता और काल की अनुकूलता पर आयोजित यह अधिवेशन परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए महायज्ञ है। अभाविप समय के साथ सतत् अपने ध्येय यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। 75वर्षों की गौरवशाली यात्रा में केवल विद्यार्थी परिषद ने प्रश्न ही नहीं अपितु उनके समाधान भी प्रस्तुत किया है और भारत के युवाओं को भारत के वास्तविक इतिहास से परिचित कराने का कार्य किया है।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि अभाविप सकारात्मक परिवर्तनों को खड़ा करने का आन्दोलन है। विद्यार्थी परिषद ने छात्राओं को आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से पूरे देशभर में मिशन साहसी चलाया। अभाविप ने कई मुद्दों पर तप, त्याग और बलिदान के बदौलत आंदोलनों का सफल नेतृत्व किया है, आज इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले है। विद्यार्थी परिषद ने 50 लाख सदस्यता का आंकड़ा पार कर लिया है, यह छात्र संगठन के रूप में परिषद के नेतृत्व में युवाओं के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण हैं।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी, सह–सरकार्यवाह मुकुंद सीआर, अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल , अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजशरण शाही, राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय सह–संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत, राष्ट्रीय अधिवेशन की स्वागत समिति अध्यक्ष निर्मल मिंडा , स्वागत समिति महामंत्री आशीष सूद, अभाविप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉ अभिषेक टंडन, प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री जी सहित विद्यार्थी परिषद् के लाखों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

'ब्रिटिश ताज' की रक्षा ही पुराने कानून की प्राथमिकता : अमित

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज लोक सभा में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 पर चर्चा का जवाब दिया, चर्चा के बाद सदन ने तीनों विधेयकों को पारित कर दिया। चर्चा के बाद सदन ने तीनों विधेयकों को पारित कर दिया।

चर्चा का जवाब देते हुए श्री अमित शाह ने कहा किआपराधिक न्याय प्रणाली को चलाने वाले लगभग 150 वर्ष पुराने तीनों कानूनों में पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले परिवर्तन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1860 में बने भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना था। उन्होंने कहा कि अब उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएंगे। उन्होंने कहा किभारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन तीन कानूनों से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।

आपराधिक न्याय प्रणाली को चलाने वाले लगभग 150 वर्ष पुराने तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले परिवर्तन किए गए हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 35 सांसदों ने इन विधेयकों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गुलामी की मानसिकता और निशानियों को जल्द से जल्द मिटाने और नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का रास्ता प्रशस्त करने का आग्रह रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्रचारी से कहा था कि कोलोनियल कानूनों से इस देश को जल्दी मुक्ति मिलनी चाहिए और उसी के तहत गृह मंत्रालय ने 2019 से इन तीनों पुराने कानूनों में परिवर्तन लाने के लिए गहन विचार–विमर्श शुरू किया था। श्री शाह ने कहा कि ये कानून एक विदेशी शासक ने अपने शासन को चलाने और गुलाम प्रजा को गवर्न करने के लिए बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि इन तीनों पुराने कानूनों के स्थान पर लाए जा रहे ये नए कानून हमारे संविधान की तीन मूल भावनाओं– व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सबके साथ समान व्यवहार के सिद्धांतों के आधार पर बनाए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि वर्तमान तीनों कानूनों में न्याय की कल्पना ही नहीं की गई है और दंड देने को ही न्याय माना गया है। उन्होंने कहा कि दंड देने का उद्देश्य पीड़ित को न्याय देना और समाज में ऐसा उदाहरण स्थापित करना है ताकि कोई इस प्रकार की गलती नकरे। श्री शाह ने कहा कि इन तीनों कानूनों का आज़ादी के इतने वर्षों बाद पहली बार मानवीकरण हो रहा है।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल ने इन तीनों कानूनों को गुलामी की मानसिकता और चिन्हों से मुक्त कराया है। उन्होंने कहा कि पुराने कानून इस देश के नागरिकों के लिए नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के राज की सुरक्षा के लिए बने थे। पुराने कानूनों में मानव वध और महिला के साथ

दुर्व्यवहार को प्राथमिकता न देकर खज़ाने की रक्षा, रेलवे की रक्षा और ब्रिटिश ताज की सलामती को प्राथमिकता दी गई थी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में सबसे पहले महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध अपराधों, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों, देश की सीमाओं की सुरक्षा, सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध, इलेक्टोरल अपराध, सिक्के, करेंसी नोट और सरकारी स्टांप के साथ छेड़खानी आदि को रखा गया है। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार हमारे संविधान की स्पिरिट के हिसाब से कानून बनने जा रहे हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने इन कानूनों में पहली बार आतंकवाद की व्याख्या कर इसके सभी लूपहोल्स खत्म कर दिए हैं। उन्होंने कहा इन कानूनों में राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया गया हैऔर साथ ही ऐसी दृढ़ता भी रखी गई है कि देश को नुकसान पहुंचाने वाले को कभी नहीं बख्शा जाएगा। श्री शाह ने कहा कि आने वाले 100 साल में होने वाले संभावित टेक्निकल इनोवेशन की कल्पना कर हमारी न्यायिक पद्धति को सुसज्ज करने के लिए सभी प्रोविज़न इन कानूनों में किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध है और इन कानूनों में उसके लिए मत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। इनमें पुलिस औऱ नागरिक के अधिकारों के बीच अच्छी तरह से संतुलन रखा गया है। सज़ा की दर बढ़ाने और साइबर क्राइम के लिए इन कानूनों में प्रोविज़न किए हैं। जेलों पर बोझ कम करने के लिए कम्युनिटी सर्विस को भी पहली बार इनमें सज़ा के रूप में शामिल कर इसे कानूनी जामा पहनाया जा रहा है।

मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय करते हुए राजद्रोह की धारा को पूरी तरह से हटाने का काम किया है और राजद्रोह की जगह देशद्रोह को रखा गया है

श्री अमित शाह ने कहा कि इन कानूनों के संबंध में कुल 3200 सुझाव प्राप्त हुए थे और इन तीनों कानूनों पर विचार के लिए उन्होंने स्वयं 158 बैठकें कीं। उन्होंने कहा कि 11 अगस्त, 2023 को इन तीनों नए विधेयकों को गृह मंत्रालय की स्थायी समिति के विचारार्थ भेजा गया था। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में तीनों नए कानून न्याय, समानता और निष्पक्षता के मूल सिद्धांतों के आधार पर लाए गए हैं। श्री शाह ने कहा कि फॉरेंसिक साइंस को इनमें बहुत तवज्जो दी गई है। इन कानूनों के माध्यम से जल्द न्याय मिले, इसके लिए इन कानूनों में पुलिस, वकील और न्यायाधीश के लिए समयसीमा रखने का काम भी किया गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 484 धाराओं वाले CrPC को रिप्लेस करने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 531 धाराएं रहेंगी, 177 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, जो IPC को रिप्लेस करेगी, में पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 358 धाराएं होंगी, 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सज़ा रखी गई है, 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड रखा गया है और 19 धाराओं को निरस्त किया गया है। इसी प्रकार, भारतीय साक्ष्य विधेयक, जो Evidence Act को रिप्लेस करेगा, में 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी, 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नई धाराएं जोड़ी गई है और 6 धाराएं निरस्त की गई हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि ये नरेन्द्र मोदी सरकार है, जो कहती है वो करती है। हमने कहा था कि धारा 370 और 35ए को हटा देंगे, हटा दिया, आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे औऱ सुरक्षाबलों को फ्री हैंड देंगे, हमने किया। उन्होंने कहा कि इन नीतियों के कारण जम्मू औऱ कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद–प्रभावित क्षेत्रों और नॉर्थईस्ट में हिंसक घटनाओं में 63 प्रतिशत और मृत्यु में 73 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के 70 प्रतिशत से ज़्यादा क्षेत्र से AFSPA को हटा लिया गया है क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हुई है। हमने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी, 2024 को राम मंदिर में राम लला विराजमान होंगे। हमने कहा था कि संसद औऱ विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देंगे, हमने सर्वानुमति से देकर देश की मातृशक्ति को सम्मानित करने का काम किया। हमने कहा था कि तीन तलाक मुस्लिम माताओं–बहनों के लिए अन्याय वाला है, उसे समाप्त कर देंगे, हमने वो वादा भी पूरा किया। हमने कहा था कि न्याय मिलने की गति को बढ़ाएंगे और न्याय दंड के आधार पर नहीं होगा, मोदी जी ने आज ये भी कर दिखाया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि न्याय एक अंब्रेला टर्म है और ये एक सभ्य समाज की नींव डालता है। उन्होंने कहा कि आज इन तीनों नए विधेयकों से जनता की न्याय की अपेक्षा को पूरा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर इस देश में भारतीय विचार की न्याय प्रणाली को प्रस्थापित करेंगे। श्री शाह ने कहा कि पहले दंड देने की सेन्ट्रलाइज़्ड सोच वाले कानून थे, अब विक्टिम–सेन्ट्रिक जस्टिस की शुरूआत होने जा रही है। ईज़ ऑफ जस्टिस को सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेह प्रोसीजर के माध्यम से साकार किया गया है और एनफोर्समेंट के लिए निष्पक्ष, समयबद्ध, एवीडेंस–बेस्ड स्पीडी ट्रायल रखा गया है जिससे अदालतों और जेलों पर बोझ कम

होगा। श्री शाह ने कहा कि जांच में फॉरेंसिक साइंस के आधार पर हमने प्रॉसीक्यूशन को बल देने का काम किया गया है और बलात्कार की पीड़ित महिला का ऑडियो–वीडियो माध्यम से बयान लेना अनिवार्य किया है। उन्होंने कहा कि ये नए कानून पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से असम तक पूरे देश में एक ही न्याय प्रणाली होगी। इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रॉसीक्यूशन का एक्सटेंशन और महत्व और उसे अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अब एक स्वतंत्र डायरेक्टर ऑफ प्रॉसीक्यूशन हर ज़िले में बनेगा, राज्यस्तर पर बनेगा जो पारदर्शिता के साथ केस में अपील का निर्णय करेगा। कई मामलों में पुलिस की जवाबदेही तय की गई है और गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना अनिवार्य रूप से हर पुलिस स्टेशन में रखनी होगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता में मानव और शरीर संबंधित अपराझओं जैसे, बलात्कार, गैंगरेप, बच्चों के खिलाफ अपराध, हत्या, अपहरण और ट्रैफिकिंग आदि को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय करते हुए राजद्रोह की धारा को पूरी तरह से हटाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह को रखा है। उन्होंने कहा कि इस देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता और इसके हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। श्री शाह ने कहा कि भारत के ध्वज, सीमाओं और संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसे निश्चित रूप से जेल जाना होगा क्योंकि नरेन्द्र मोदी सरकार का थ्रस्ट है कि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि हमने देशद्रोह की परिभाषा में उद्देश्य और आशय की बात की है और अगर उद्देश्य देशद्रोह का है, तो आरोपी को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस नई पहल को अपना रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार संविधान की स्पिरिट के हिसाब से चलने वाली सरकार है और अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा तो उसे सज़ा ज़रूर होगी। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हज़ारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों को देश से निकालने के लिए राजद्रोह के आरोप में अपने जीवन का स्वर्णकाल जेल में काटा, आज नरेन्द्र मोदी सरकार की इस पहल से उनकी आत्मा को ज़रूर संतुष्टि मिलेगी कि आज़ाद भारत में आज इस अन्यायिक प्रोविज़न को समाप्त कर दिया गया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी इन कानूनों में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता में इस बारे में एक नया चैप्टर जोड़ा गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार के अपराध में आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गैंगरेप के मामलों में 20 साल या ज़िंदा रहने तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। श्री शाह ने कहा कि आज़ादी के 75 सालों के बाद पहली बार आतंकवाद को आपराधिक न्याय प्रणाली में जगह देने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी ही मानवाधिकार का हनन करता है और उसे कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, ज़हरीली गैस, न्यूक्लीयर का उपयोग जैसी घटनाओं में कोई भी मृत्यु होती है, तो इसका ज़िम्मेदार आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिभाषा से इस कानून के दुरुपयोग की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है, लेकिन जो आतंकवादी कृत्य करते हैं उन्हें कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए और इस सदन द्वारा इस धारा के अनुमोदन से आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का एक संदेश जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि इन कानूनों में संगठित अपराध की भी पहली बार व्याख्या की गई है। उन्होंने कहा कि गैरइरादतन हत्या के मामले में पुलिस के पास जाने और पीड़ित को अस्पताल ले जाने के मामले में कम सज़ा का प्रावधान किया है। श्री शाह ने कहा कि हिट एंड रन केस में हमने 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया है।

टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमने भारत की न्यायिक व्यवस्था को दुनिया में सबसे अत्याधुनिक बनाने का काम किया है

गृह मंत्री ने कहा कि अब पुलिस को शिकायत के 3 दिनों में ही FIR दर्ज करनी होगी और 3 से 7 साल की सज़ा वाले मामले में प्रारंभिक जांच करके एफआईआर दर्ज करनी होगी। उन्होंने कहा कि अब हमने बिना किसी देर के बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट को 7 दिनों के अंदर पुलिस थाने और न्यायालय में सीधे भेजने का प्रावधान किया है। अब चार्जशीट दाखिल करने की समयसीमा तय कर इसे 90 दिन रखा गया है और इसके बाद और 90 दिन ही आगे जांच हो सकेगी। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट को 14 दिनों में मामले का संज्ञान लेना ही होगा और कार्रवाई शुरू हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि आरोपी द्वारा आरोपमुक्त होने का निवेदन भी 60 दिनों में ही करना होगा। उन्होंने कहा कि कई मामले ऐसे हैं जिनमें 90 दिनों में आरोपी की अनुपस्थिति में भी ट्रायल कर उन्हें सज़ा सुनाई जा सकेगी। अब मुकदमा खत्म होने के 45 दिनों में ही न्यायाधीश को निर्णय देना होगा। इसके साथ ही निर्णय और सज़ा के बीच 7 ही दिनों का समय मिलेगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने के 30 दिनों के अंदर ही दया याचिका दाखिल की जा सकती है।

श्री अमित शाह ने कहा कि e-FIR से कोई भी महिला थाने में एफआईआर करा सकती है, उसका संज्ञान भी लिया जाएगा और दो दिन के अंदर ही घर आकर इसका जवाब लेने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग भी पुलिस के अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि क्राइम सीन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के तीनों चरण में हमने टेक्नोलॉजी के उपयोग को तवज्जो दी है, जिससे पुलिस जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही तो निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी ही, सबूत की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और विक्टिम और आरोपी दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी। एविडेंस, तलाशी और जब्ती में वीडियो रिकॉर्डिंग का कंपलसरी प्रोविजन किया गया है, जिससे किसी को फ्रेम करने की संभावनाओं में बहुत कमी आएगी। श्री शाह ने कहा कि बलात्कार के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी करने का निर्णय नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारे यहां दोष सिद्धि की दर बहुत कम है और इसे बढ़ाने के लिए साइंटिफिक एविडेंस पर थ्रस्ट देना पड़ेगा। इस बिल में क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सुधार करने, इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक पद्धति से करने और 90% का कन्विक्शन रेट का लक्ष्य रखते हुए हमने प्रावधान किया है कि 7 साल से ज्यादा सजा वाले अपराधों में FSL टीम का विज़िट कंपलसरी होगी। श्री नरेन्द्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, जब प्रधानमंत्री बने तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई और नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के तहत अब तक 9 राज्यों में एनएफएसयू के 7 परिसर और दो ट्रेनिंग अकादमी खुल चुके हैं। 5 साल बाद हर साल 35000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमें मिलेंगे जो हमारी ज़रूरत को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 6 अत्याधुनिक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री बना रही है।

श्री अमित शाह ने कहा कि अब पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर ज़ीरो एफआईआर करा सकता है और वो 24 घंटे में संबंधित पुलिस स्टेशन में अनिवार्य रूप से ट्रांसफर करनी होगी। इसके साथ ही हर जिले और थाने में पुलिस अधिकारी को पदनामित किया है जो गिरफ्तार लोगों की सूची बनाकर उनके संबंधियों को इन्फॉर्म करेगा। श्री शाह ने कहा कि जमानत और बांड को स्पष्ट नहीं किया गया था, लेकिन अब जमानत और बांड को स्पष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की के लिए भी प्रावधान किया गया है। पहले 19 अपराधों में ही भगोड़ा घोषित कर सकते थे, अब 120 अपराधों में भगोड़ा घोषित करने का प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ट्रायल इन एब्सेंशिया के तहत अब अपराधियों को सज़ा भी होगी और उनकी संपत्ति भी कुर्क होगी। एक तिहाई कारावास काट चुके अंडर ट्रायल कैदी के लिए जमानत का प्रोविजन किया गया है। उन्होंने कहा कि सजा माफी को भी तर्कसंगत बनाने का काम किया गया है। अगर मृत्यु की सजा है तो ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकेगी। आजीवन कारावास है तो 7 साल की अवधि सज़ा भोगनी ही पड़ेगी और 7 वर्ष या उससे अधिक सजा है तो कम से कम 3 साल जेल में रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में पड़ी हुई संपत्ति की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी मजिस्ट्रेट को करवाकर अदालत की सहमति से 30 दिनों के अंदर इसे बेच दिया जाएगा और पैसे कोर्ट में जमा होंगे। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने भारतीय साक्ष्यो अधिनियम में कई बदलाव किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज की परिभाषा में शामिल कर दिया है और अब किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज माना जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान को साक्ष्य की परिभाषा में शामिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब इसका पूर्ण अमल देश के हर थाने में हो जाएगा तब हमारी न्यायिक प्रक्रिया दुनिया में सबसे आधुनिक न्याय प्रक्रिया हो जाएगी। श्री अमित शाह ने कहा कि अब तक ICJS के माध्यम से देश के 97% पुलिस स्टेशन को कम्प्यूपिक राइज्डि करने का काम समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अदालतों का भी आधुनिकीकरण हो रहा है और आईसीजेएस के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, थाना, गृह विभाग, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ऑफिस, जेल और कोर्ट एक ही सॉफ्टवेयर के तहत ऑनलाइन होने की कगार पर हैं। इसके साथ ही स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेज वेबसाइट और लोकेशनल साक्ष्य को सुबूत की परिभाषा में शामिल किया गया है और आरोपियों, विशेषज्ञों पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित होने की अनुमति दी है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि एक आतंकवादी कृत्य के लिए एक ही जगह गुनाह रजिस्टर होगा, लेकिन CrPC में आज तक आतंकवाद की व्याख्या नहीं की गई थी और बचकर निकल जाते थे, उनके बचने के सारे रास्ते इस कानून के माध्यम से हमने बंद कर दिए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि दया का अधिकार उसी का बनता है जो अपने कृत्य पर पछतावा करता है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक साइंस को इतनी दृढ़ता के साथ कानून में जगह देने वाला एकमात्र देश भारत होगा। श्री शाह ने कहा कि ब्रिटिश काल के सारे गुलामी के चिन्होंन को समाप्त कर अब ये संपूर्ण भारतीय कानून बनने जा रहा है।

श्री नरेन्द्र मोदी
17 दिसम्बर, 2023
नमो घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

17 दिसम्बर, 2023
17 டிசம்பர், 2023

98.08
करोड़ रुपये
वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अवसर पर
₹19 हजार करोड़ से अधिक की 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास

वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अवसर पर
₹19 हजार करोड़ से अधिक की 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91, शीर्षक कोडः UPHIN16701, डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2022-23
दिसम्बर विकसित भारत संयुक्त विशेषांक 2023 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 26–29 (द्वितीय पाक्षिक)

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।